घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 23, अंक - 19- शनिवार 21- नवम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उद्घाटन किया

दुनिया में युद्ध-अशांति पर चर्चा...हम भारत में सिविलाइजेशन डायलॉग कर रहे : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम दिल्ली के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब दुनिया में युद्ध और अशांति पर चर्चा हो रही है,तब भारत में सभ्यताओं के बीच संवाद हो रहा है। पीएम ने कहा- दुनिया इस समय उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। ऐसे में सांस्कृतिक जुड़ाव और सहयोग से शांति का रास्ता मजबूत हो सकता है। कार्यक्रम में शामिल पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने कहा- मुझे उम्मीद है कि इस फोरम के बाद भारत-पाकिस्तान समेत सभी देशों के रिश्ते बेहतर होंगे।

पीएम बोले- भारत में विविधता ही एकता का आधार

पीएम ने कहा...हम हेरिटेज सर्किट की संभावनाएं तलाश सकते हैं। इससे लोगों को कई देशों की संस्कृति जानने का मौका मिलेगा। युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। हम क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सांस्कृतिक विरासत दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा...भारत में हम विविधता को स्वीकार करते हैं और उसका उत्सव मनाते हैं। जब हम उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारी विविधता ही एकता का आधार बन जाती है। हमें साथ चलना चाहिए,आपस में संवाद करना चाहिए और विचारों में तालमेल बनाना चाहिए।



पीएम मोदी बोले- डिजिटल माध्यमों से सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने के मौके

मोदी ने कहा...भारत के महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के विचार विदेशों तक पहुंचे और सूफी परंपरा ने भारत में कव्वाली को विकसित किया देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की यह प्रक्रिया आज भी जारी रहनी चाहिए। ऐसे में सृष्ट्ह जैसे मंचों की भूमिका अहम हो जाती है। पीएम ने कहा- डिजिटल माध्यमों ने सांस्कृतिक जुड़ाव की नई संभावनाएं पैदा की हैं। अब अलग-अलग देशों के लोग कुछ ही मिनटों में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। सृष्ट्ह देशों को इन संभावनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

पीएम बोले- ट्रेड रूट्स ने भारत,चीन और मध्य एशिया को जोड़ा

पीएम ने कहा- आज दुनिया में पीपल-टू-पीपल कनेक्ट की चर्चा होती है। करीब 5 हजार साल पहले सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार होता था। भारत,चीन और मध्य एशिया ट्रेड रूट्स से जुड़े थे। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के आदान-प्रदान के केंद्र बने।

पुराना किला में दो प्रदर्शनियां भी लगाई गईं

प्रधानमंत्री ने उद्घाटन से पहले पुराना किला में दो प्रदर्शनियां देखीं। इनमें पहली प्रदर्शनी 'महाभारत स्क्रॉल पवेलियन- अनंतः 18वीं सदी की दुर्लभ महाभारत पांडुलिपि' पर आधारित है। दूसरी प्रदर्शनी 'अस्तित्वः द एसेंस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस' में दिल्ली के इतिहास को दिखाया गया है। इसमें 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के इतिहास को शामिल किया गया है।

सांस्कृतिक और सभ्यतागत सहयोग से देशों के रिश्ते मजबूत होंगे : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ ने कुछ महीने पहले ही अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए हैं। ऐसे में सांस्कृतिक और सभ्यतागत सहयोग सदस्य देशों के संबंधों को और मजबूती देगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फोरम के जरिए एक नई परंपरा की शुरुआत होगी और इसे ऐतिहासिक बनाया जाएगा। पीएम ने दिल्ली के पुराना किला का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर है और इसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में बौद्ध दर्शन की प्रस्तुति और हनुमान जी की यात्रा के जरिए प्रेम और एकता का संदेश दिया गया। मोदी ने कहा कि प्रेम और एकता की ये शिक्षाएं जितनी प्राचीन हैं, उतनी ही सार्वभौमिक भी हैं। ये लोगों को सहज ही एक-दूसरे से जोड़ती हैं और आज के समय की मांग भी हैं।

पीएम बोले...दुनिया में युद्ध-अशांति पर चर्चा हावी

पीएम मोदी ने कहा...यह पहला एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। जब दुनिया में युद्ध और अशांति पर चर्चा हावी है,तब हम भारत में सभ्यताओं के बीच संवाद कर रहे हैं। यह इसलिए भी अहम है, क्योंकि वैश्विक शांति के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव जरूरी है।

फारूक अब्दुल्ला बोले- पाकिस्तानी मंत्री का भारत आना अच्छी शुरुआत : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एससीओ फोरम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक के भारत आने का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की नई शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि पुराने मुद्दों को फिर उठाने के बजाय शांति और बातचीत पर ध्यान देना चाहिए।

अब्दुल्ला ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि बातचीत से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।

आंध्र प्रदेश-ओडिशा के तट से टकराया चक्रवात अकवान

90kmph की रफ्तार से हवाएं चल रहीं ओडिशा-आंध्र में भारी बारिश,4 लाख लोग शिफ्ट

भुवनेश्वर/विशाखापट्टनम,20 नवम्बर 2026। चक्रवाती तूफान अकवान शुक्रवार को सुबह करीब 7.30 से 8:30 बजे के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच गोपालपुर तट से टकराया। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 90kmph रही। तूफान के असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा में करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इनके लिए 9,341 राहत शिविर बनाए गए हैं। साथ ही 423 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। तूफान के चलते पूर्वी रेलवे ने 41 और दक्षिण पूर्व रेलवे ने 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी हैं। वहीं, 29 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। तूफान का असर 10 राज्यों में पड़ सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड में भी मौसम बदल सकता है और बारिश हो सकती है। ओडिशा के गंजाम जिले में तारासिंग पुलिस थाने की टीम ने भारी बारिश के बीच घने जंगल और दुर्गम रास्तों से एक बुजुर्ग व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। चक्रवात 'अकवान' के असर से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम को देखते



हुए गंगासागर में प्रशासन लगातार घोषणाएं कर रहा है और तीर्थयात्रियों व पर्यटकों से समुद्र तट खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है।

झारखंड के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट : मौसम विभाग ने झारखंड में शुक्रवार को तेज बारिश, बिजली गिरने और 50 kmph की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई है।

ओडिशा सरकार बोली- राज्य में बड़ा नुकसान नहीं : ओडिशा में साइक्लोन अकवन से अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर सुरेश पुजारी ने यह जानकारी दी। वहीं, राज्य की चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने बताया कि अब तक करीब 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है।

केंद्र ने दी 1.75 लाख नए शहरी मकानों को मंजूरी,1.5 लाख को सैद्धांतिक स्वीकृति

नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1.75 लाख नए मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा 1.5 लाख मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गयी है। इसके साथ ही योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 11वीं बैठक 19 नवंबर को शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मकानों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में असम, गोवा, गुजरात,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान,तमिलनाडु,उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लाभार्थी आधारित निर्माण तथा भागीदारी में किफायती आवास श्रेणियों के तहत 1.75 लाख मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें असम के 4,841, गोवा के छह,



गुजरात के 5,793, मध्य प्रदेश के 10,913, महाराष्ट्र के 19,778, ओडिशा के 2,681, पुडुचेरी के 937, राजस्थान के 4,572, तमिलनाडु के 14,350, उत्तर प्रदेश के 1,01,493 और पश्चिम बंगाल के 10,159 मकान शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,27,349 और महाराष्ट्र में 22,484 मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इन प्रस्तावों पर अंतिम स्वीकृति संबंधित राज्यों की ओर से जरूरी अनुपालन और योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर निर्भर होगी। सचिव सतेंद्र सिंह ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृत धनराशि का समय पर उपयोग करने और लाभार्थियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को समय से राशि जारी करने को कहा। उन्होंने मकानों की निगरानी मजबूत करने,जियो-टैगिंग और लंबित आवेदनों का तय समय में सत्यापन पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को किफायती आवास के लिए व्यापक नीतियां बनाने और जरूरी सुधार लागू करने की सलाह दी गई। योजना में महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत समाज के कमजोर वर्गों की आवास जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 सितंबर 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के एक करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने या खरीदने में सहायता देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और इसके दूसरे चरण के तहत अब तक कुल 1.29 करोड़ मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1.01 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

मदुरै की थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को जलेगा दीपम

सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी,आम लोगों की एंट्री पर रोक,रस्म को लेकर दरगाह-मंदिर में विवाद



नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित सुब्रमण्य स्वामी मंदिर प्रशासन को थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर प्राचीन पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने यह इजाजत सिर्फ 24 नवंबर को यानी इस साल के लिए एक बार दी है। हालांकि, दीप जलाने के लिए केवल मंदिर प्रशासन की सीमित टीम और अधिकृत अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी। आम लोगों की एंट्री पर रोक रहेगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर भी रोक लगाई है। दरअसल, दीपथून पर दीप जलाने को लेकर मंदिर और पहाड़ी के पास स्थित हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दीपथून दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है। कई दशकों से मंदिर में कार्तिगई दीपम पहाड़ी की निचली ढलान पर बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। हिंदू संगठनों की मांग है कि दीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून पर जलाया जाए, जबकि दरगाह प्रबंधन निचली ढलान पर दीप जलाने की पुरानी परंपरा का हवाला देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई अहम कानूनी सवाल जुड़े हैं। इनमें अलग-अलग धार्मिक दावे, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में अदालत की समीक्षा की सीमा शामिल है।

भोपाल में बनी बर्ड फ्लू की दुनिया की पहली वैक्सीन...1-2 रुपए होगी एक डोज की कीमत,शिवराज बोले...300 करोड़ में बनेगी BSL-4 लैब

भोपाल,20 नवम्बर 2026। भोपाल के वैज्ञानिकों ने मुर्गियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को इसे देश को समर्पित किया। एक डोज की कीमत 1 से 2 रुपए होगी। पहली डोज के 21 दिन बाद बूस्टर देना होगा और इसका असर 6 महीने तक रहेगा। शिवराज ने भोपाल के ICAR-NIHSAD में 300 करोड़ रुपए की लागत से BSL-4 लैब बनाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वैक्सीन बनाने के दौरान वैज्ञानिकों को कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ा। घर पहुंचने पर उन्हें 120 लीटर पानी से नहाना पड़ता था। रिसर्च के दौरान घर में



पालतू जानवर रखने की भी मनाही थी। शिवराज ने वैक्सीन को जल्द बाजार में लाने के निर्देश दिए। इसके लिए तकनीक एग्रीनोवेट इंडिया के जरिए व्यावसायिक उत्पादन के लिए दी जाएगी। ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट के मुताबिक, H5N1 के इस वैरिएंट की यह दुनिया की पहली वैक्सीन है।

शिवराज बोले...पशु चलते-फिरते एटीएम हैं...

शिवराज सिंह चौहान ने कहा- पशुपालन किसानों की कमाई का बड़ा जरिया है। पशुओं में बीमारियों से किसानों को भारी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि पशुओं की बीमारियों से हर साल करीब 56 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता है। शिवराज ने कहा- मुंहपका-खुरपका से 22 हजार करोड़, लंपी से 20 हजार करोड़,ब्रुसेलोसिस से 9,212 करोड़ और पीपीआर से 4,683 करोड़ रुपए का नुकसान शामिल है। शिवराज ने कहा- वैक्सीन की तकनीक एग्रीनोवेट इंडिया के जरिए व्यावसायिक उत्पादन के लिए दी जाएगी।

2047 में भोपाल का योगदान याद रखा जाएगा...

खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा- यह वैक्सीन 'जय जवान-जय किसान,जय विज्ञान और जय अनुसंधान' की सोच का नतीजा है। उनके भाई ने जब पोल्ट्री व्यवसाय शुरू किया था, तब बर्ड फ्लू सबसे बड़ा डर था। विकसित भारत 2047 में भोपाल का योगदान याद रखा जाएगा। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा- इस उपलब्धि से भोपाल को दुनिया में गौरव मिला है।

योगी आदित्यनाथ की मां का निधन,91 साल की थीं

देहरादून,20 नवम्बर 2026। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 91 साल की थीं। सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं। पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली। उस वक्त घर में योगी के भाई महेंद्र और उनका परिवार मौजूद था। आज ऋषिकेश के संपूर्णानंद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र ने बताया कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है। हमने उन्हें



मैसेज छोड़ा है। बाकी भाइयों और रिश्तेदारों को इंतजार कर रहे हैं। कल ऋषिकेश में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह माता जी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो एक साल से कुछ नहीं बोल पाती थीं। जिस वक्त सावित्री देवी का विधन हुआ उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में सशक्त युवा, समृद्ध उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखा- मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है।

दिल्ली में 26 नवंबर को लगेगी डाक अदालत 24 नवंबर तक भेजनी होगी शिकायत...

नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। दिल्ली में डाक सेवाओं से जुड़ी लंबित शिकायतों के निपटारे के लिए 26 नवंबर को सर्किल स्तर की डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें केवल दिल्ली की मंडलीय स्तर की डाक अदालतों में उठाई गई उन शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जिनका अब तक समाधान नहीं हुआ है। डाक विभाग के दिल्ली सर्किल के अनुसार डाक अदालत का आयोजन नई दिल्ली के झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास मेघदूत भवन स्थित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय की तीसरी मंजिल पर सुबह 11 बजे किया जाएगा।

इसमें प्रत्येक शिकायतकर्ता की समस्या पर व्यक्तिगत रूप से विचार कर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

संपादकीय

भवनों के ढांचे में नवाचार

भारत में इमारतों की ऊंचाइयां जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं,जमीन और आसमान- दोनों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज शहरी विकास की चर्चा मुख्य रूप से स्मार्ट और हरित (पर्यावरण-अनुकूल) निर्माण पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में पिछले तीन दशकों के दौरान एक बड़ा बदलाव दिखा है,जहां सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) अब कोई गौण विषय नहीं, बल्कि आर्किटेक्चरल डिजाइन और बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा बन गई है। ऊर्जा की बढ़ती लागत, लंबे समय में किफायती होना,सस्टेनेबिलिटी से जुड़े वादे और पर्यावरण-अनुकूल व उच्च-क्षमता वाली इमारतों की मांग-ये कुछ ऐसे कारक हैं जो इस बदलाव को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी) के अनुसार,पारंपरिक इमारतों की तुलना में ग्रीन बिल्डिंग्स 20 से 30 प्रतिशत कम ऊर्जा की खपत करती हैं। सरकारी स्रोतों के अनुसार,भारत के वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी लाने और 2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी (कार्बन तटस्थता) हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में ग्रीन बिल्डिंग्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आइजीबीसी), ग्रीन रेटिंग फार इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट और वैश्विक स्तर पर एलईईडी (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायर्नमेंटल डिजाइन) जैसे मानक और प्रमाणन एक ढांचा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा की खपत,पानी के इस्तेमाल,कचरा प्रबंधन और इनडोर पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे पैमानों के आधार पर किसी इमारत का मूल्यांकन करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग में लंबे समय से सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी दिखाई देने वाली चीजों पर ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी (स्थिरता) पर काम करते समय, डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग के मुख्य सिस्टम में नए अवसर तलाश रहे हैं। यहीं पर लिफ्ट और एस्केलेटर एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर इमारतों में बहुत अधिक उपयोग होने वाले सिस्टम हैं, जो लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। ये किसी इमारत के रोजमर्रा के कामकाज का एक अहम हिस्सा हैं, जो ऊर्जा की खपत,लोगों के आराम,पहुंच,सुरक्षा और कुल कार्यक्षमता पर असर डालते हैं। स्मार्ट लिफ्ट किसी इमारत के सेंट्रल नर्वस सिस्टम (केंद्रीय तंत्रिका तंत्र) की तरह काम कर सकती हैं, ये डाटा और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करके परफार्मेंस को बेहतर बनाती हैं और ऊर्जा की बचत में मदद करती हैं। इस तरह ये अधिक स्मार्ट,कुशल और टिकाऊ इमारतों के निर्माण में एक बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। यह कार्यक्षमता भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए डिजाइन का परिणाम है। इसके अलावा,एलईडी लाइटिंग,उच्च-क्षमता वाली मोटरें और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (जहां लागू हो) बिजली की खपत को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायक हो सकते हैं।

टेलीविजन : मनोरंजन के साथ सूचना,शिक्षा एवं शांति का सशक्त माध्यम


प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा,उत्तरप्रदेश


प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

विश्व में शांति,सुरक्षा,सहयोग, समन्वय,संस्कार,सामूहिकता,सहकारिता के उदात्त भावों के संवर्धन तथा संघर्ष,हिंसा,युद्ध,रक्तपात,अराजकता से मुक्त खुशहाल एवं समृद्ध वैश्विक परिवेश का निर्माण करने तथा सभी देशों के मध्य पारस्परिक सामंजस्य स्थापित कर विकास पथ पर बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु 24 अक्टूबर, 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ वर्ष के बारह महीनों में कुछ महत्वपूर्ण दिवसों का थीम आधारित वैश्विक आयोजन कर जन-जागरूकता का प्रसार करता है,ताकि प्रकृति का संरक्षण हो और यह खूबसूरत दुनिया मानव एवं पशु-पक्षियों के लिए रहने लायक बनी रहे। प्रत्येक वर्ष 21 नवम्बर को मनाया जाने वाला विश्व टेलीविजन दिवस इस शृंखला का एक विशिष्ट जागतिक कार्यक्रम है जो मनोरंजन के साथ ही शिक्षा,सूचना,संस्कृति के प्रसार तथा शांति एवं सौहार्द स्थापना के अपने उद्देश्यों को अपनाने हेतु सामान्य जन को प्रेरित करता है। विश्व टेलीविजन दिवस वास्तव में सामाजिक विकास एवं जागरूकता के प्रति टेलीविजन के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मुद्दों पर जनमत बनाने में उसकी भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 21 एवं 22 नवम्बर, 1996 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया गया था,जिसमें विभिन्न देशों के टेलीविजन मीडिया कर्मियों,टेलीफिल्म एवं सीरियल तथा वृत्तचित्र निर्माताओं ने सहभागिता कर टेलीविजन संसाधन एवं टेली पत्रकारिता का मानवता के कल्याण एवं पर्यावरण संरक्षण सहित मनोरंजन, राजनीति,शिक्षा,संस्कृति,आर्थिकी, समाज-रचना में योगदान तथा हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लोक जागरण एवं सामान्य वातावरण के निर्माण में भूमिका विषयक अनुभवों का आदान-प्रदान किया था। इस आयोजन की सफलता से उत्साहित संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 17 दिसम्बर,1996 को एक प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 21 नवम्बर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने की घोषणा की थी, जो अद्यावधि गतिमान है।

विश्व टेलीविजन दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक महत्वपूर्ण दिवस है जो दुनिया में व्यक्तियों एवं राष्ट्रों को पारस्परिक संघर्ष, हिंसा एवं रक्तपात से दूर रहने तथा मेल-जोल बढ़ा कर शांति एवं विश्व बंधुत्व के मानवीय मूल्यों से प्रकाशित पथ पर सतत बढ़ने को प्रेरित एवं उत्साहित करता है। सजीव सूचनाओं के तत्काल सम्प्रेषण में टेलीविजन खरा उतरा है और आम आदमी घटनाओं से जुड़ वास्तविकता का दर्शन कर स्थिति की संवेदनशीलता का अनुभव कर पाने में समर्थ हुआ है। यह समझ उसे बेहतर दुनिया रचने में मदद करती है। विद्यालयों में बच्चे किताबों के साथ-साथ टेलीविजन के माध्यम से अपनी क्षमताओं एवं कौशलों की धार तेज कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आज दुनिया के किसी भी दृश्य,घटना और आयोजन से घर बैठे जुड़ना सहज सम्भव हुआ है।

टेलीविजन की यह रोचक यात्रा अब एक शताब्दी की हो गई है। वर्ष 1924 में स्कॉटलैंड के विज्ञानी जॉन लोगी बेयर्ड ने पहला टेलीविजन बनाया था। अपने इस यांत्रिक टेलीविजन के माध्यम से बेयर्ड ने लंदन में मार्च 1925 तथा जनवरी 1926 में चलती-फिरती चित्रावली का सार्वजनिक प्रदर्शन किया,किंतु स्क्रीन पर चित्र बहुत धुंधले आये थे। इसे बेहतर कर 1927 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन बनाया अमेरिका के फिलो टेलर फार्नसवर्थ ने,जो आधुनिक टेलीविजन तकनीकी का आधार बना। विश्व में पहला टेलीविजन स्टेशन न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया। बीबीसी ने 1936 में पहली बार टेलीविजन का नियमित प्रसारण आरंभ किया। निस्संदेह टेलीविजन ने विराट विश्व को मानव के सम्मुख एक निर्जीव मशीन की स्क्रीन पर सजीव उपस्थित कर दिया है।

भारत में टेलीविजन सेवा का आरंभ यूनेस्को के सहयोग से स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दशक बाद हो सका था, जब 15 सितम्बर,1959 को दिल्ली में पहला प्रसारण आल इंडिया रेडियो अंतर्गत सम्भव हुआ था। आकाशवाणी भवन में ही टेलीविजन आडिटोरियम का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस सेवा को नाम दिया गया टेलीविजन इंडिया जिसे 1975 में बदल कर दूरदर्शन कर दिया गया। तब सप्ताह में दो बार एक-एक घंटे का कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था। कार्यक्रमों में मुख्यतः नागरिकों के कर्तव्य,सड़क यातायात के नियम एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल होते थे। आगे इस कड़ी में कृषि एवं ग्रामीण विकास,परिवार नियोजन, सामाजिक जागरूकता,विज्ञान, समाचार तथा सम-सामयिक विषयों पर सांस्कृतिक,शैक्षिक एवं सामुदायिक शिक्षण जैसे विषयों को जोड़ा गया। वर्ष 1980 तक देश के शहरों एवं कस्बों के बड़े हिस्से तक टेलीविजन की पहुंच अवश्य हो गई किंतु ग्रामीण वनवासी क्षेत्र टेलीविजन की परिधि में न आ सके। देश में 15 अगस्त,1982 को पहली बार टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण का आरंभ हुआ। तब तक टेलीविजन शिक्षा, समाचार एवं मनोरंजन का एक अच्छा साधन बन चुका था। और तभी 7 जुलाई, 1984 को टेलीविजन पर पहला धारावाहिक नाटक हम लोग का प्रसारण हुआ जो बहुत लोकप्रिय हुआ और जिसके 156 एपीसोड प्रसारित हुए। आगे रामायण और महाभारत धारावाहिक ने टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में सर्वाधिक दर्शकों द्वारा देखे जाने वाले धारावाहिकों के रूप में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गये। इंटरनेट की सुविधा सुलभ होने से टेलीविजन के एंटीना की भी जरूरत नहीं रही और टेलीविजन प्रसारण नगर, ग्राम, गिरि, कानन, सागर,घाटी तक सुगमता से सम्भव हो सका है।

आज तो पूरी दुनिया में टेलीविजन पर समाज जीवन के विविध क्षेत्रों के अनेकानेक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं जो विभिन्न आयु वर्ग के दर्शकों द्वारा रुचिपूर्वक देखे जा रहे हैं। क्रिकेट, फुटबाल,हॉकी आदि के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मैचों,बिम्बलडन,एशियाड, ओलम्पिक खेलों,राकेट प्रक्षेपण,अंतरिक्ष प्रयोगशाला एवं चंद्रयान मिशन,युद्धों, कुम्भ एवं अन्यान्य मेलों,प्राकृतिक आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्यों,धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजनों आदि के सजीव प्रसारण ने पूरी दुनिया को मानो स्क्रीन पर उतार दिया हो। टेलीविजन के कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों में पर्यावरण सुरक्षा, लोक चेतना, नागरिक कर्तव्य बोध तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावधारा मानवीय मूल्यों एवं सदुणों से समृद्ध हो रही है। टेलीविजन दिलों की दूरियां कम करके स्नेह-प्रेम,करुणा,ममता-समता एवं समरसता का मृदुल प्रसाद बांट रहा है। शांति, सौहार्द एवं सौजन्यता के स्वर आलाप रहा है जो व्यक्ति,समाज एवं देश को हिंसक मनोवृत्ति के त्यागने तथा प्रेम एवं अहिंसा के पथ पर सतत अग्रसर होने का पथ प्रशस्त कर रहा है।

भूखा ना रहे अबोध बचपन

भुखमरी किसी भी देश का दुर्भाग्य

समग्र मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा कि वहां के निवासियों के अबोध बच्चे भूखे और कुपोषण के शिकार हो रहे हों।भारत जैसे विकासशील के संदर्भ में यह बात और भी गंभीर हो जाती है जहां इतनी बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग निवास करते है,खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को भोजन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसकी वैश्विक स्थिति भी काफी भयावह है ।आर्थिक विकास की चमक के पीछे छिपी भूख,कुपोषण और सामाजिक असमानता की पीड़ाकिसी राष्ट्र की सभ्यता,संस्कृति और विकास का वास्तविक मूल्यांकन उसकी ऊँची इमारतों,चमचमाती सड़कों,औद्योगिक उत्पादन अथवा डिजिटल उपलब्धियों से नहीं किया जा सकता। किसी देश की वास्तविक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसके नागरिकों को सम्मानपूर्वकजीवन जीने के लिए भोजन,शक्षा,स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं या नहीं। विशेषकर उस देश की नैतिक और


संजीव कुमार ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़



सामाजिक स्थिति का आकलन इस बात से होना चाहिए कि उसके अबोध बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे हैं। जिस देश में बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हों, माताएँ अपने शिशुओं को पर्याप्त पोषण देने में असमर्थ हों और बुजुर्ग दो वक्त की रोटी के लिए दूसरों पर निर्भर हों,वहाँ विकास के तमाम दावों पर गंभीर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। भूख केवल पेट की समस्या नहीं,यह सामाजिक असमानता है। आर्थिक विषमता और मानवीय संवेदनाओं के कमजोर पड़ने का भी संकेत है।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक और विकासशील देश के लिए यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण है। एक ओर हम विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं,अंतरिक्ष विज्ञान,सूचना प्रौद्योगिकी,औद्योगिक उत्पादन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों का कुपोषण हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। आखिर विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बावजूद भोजन और पोषण की समस्या क्यों बनी हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर केवल सरकारी योजनाओं में नहीं, बल्कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं और सामाजिक व्यवस्था में भी तलाशना होगा। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि नवंबर 2026 तक उपलब्ध ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है और उसका स्कोर 24.1 है। इसे गंभीर श्रेणी में रखा जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्पपोषण की दर 9.8 प्रतिशत,पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन 29.3 प्रतिशत और दुबलापन 19 प्रतिशत है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। विशेष रूप से बच्चों में दुबलेपन की ऊँची दर देश की पोषण व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। यह भी समझना जरूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स केवल भूखे लोगों की संख्या नहीं बताता,बल्कि अल्पपोषण,बच्चों के शारीरिक विकास और बाल मृत्यु जैसे संकेतकों के माध्यम से भूख की व्यापक स्थिति को सामने रखता है। भारत की स्थिति को केवल वैश्विक रैंकिंग के नजरिये से देखा जाना पर्याप्त नहीं होगा,लेकिन इन आँकड़ों को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। हमें यह समझना होगा कि खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में अंतर है। किसी देश के गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार होना इस बात की गारंटी नहीं है कि प्रत्येक नागरिक की थाली में पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (2023-24) के परिणामों ने भारत के सामने एक मिली-जुली तस्वीर प्रस्तुत की है। मई 2026 में जारी इस सर्वेक्षण में लगभग 6.79 लाख परिवारों और 715 जिलों को शामिल किया गया। इसके अनुसार पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन 35.5 प्रतिशत से घटकर 29.3 प्रतिशत हुआ है। गंभीर दुबलापन भी 7.7 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत रह गया है। यह निश्चित रूप से सकारात्मक उपलब्धि है। लेकिन दूसरी ओर, कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 32.1 से घटकर केवल 31.8 प्रतिशत हुआ है। इसका अर्थ है कि आज भी लगभग हर तीन में से एक बच्चा अपनी उम्र के अनुपात में कम वजन का है। कुल दुबलेपन की समस्या भी लगभग 19 प्रतिशत पर बनी हुई है। बच्चों को जन्म के बाद उचित पोषण, संतुलित आहार और समय पर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता अब भी बनी हुई है।

हमारी पर्सनैलिटी से पता चलता है हमारा स्टेटस

बाहरी रूप और आंतरिक व्यक्तित्व का संगम

जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, तो जाने-अनजाने हमारा ध्यान सबसे पहले उसके बाहरी व्यक्तित्व पर जाता है। उसकी चाल-ढाल, पहनावा,बातचीत का सलीका और आत्मविश्वास,ये सब मिलकर एक ऐसी अदृश्य भाषा रचते हैं, जो बिना एक भी शब्द कहे बहुत कुछ बयान कर देती है। अक्सर कहा जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी से हमारे स्टेटस का अंदाज़ा होता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो स्टेटस का अर्थ केवल धन-दौलत या पद-प्रतिष्ठा नहीं है, यह हमारी रुचियों, संस्कारों, अनुशासन और आत्म-सम्मान का प्रतिबिंब है।


डॉ. मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

पहनावा और जूते : सलीके का पहला आईना

कपड़े केवल तन ढकने या मौसम से बचने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सोच और सलीक़े को भी दर्शाते हैं। स्वच्छ,सुव्यवस्थित और अवसर के अनुकूल कपड़े पहनना यह बताता है कि व्यक्ति स्वयं का और सामने वाले का कितना सम्मान करता है। इसी तरह जूतों की बात करें, तो एक पुरानी कहावत है कि किसी इंसान के बारे में जानना हो तो उसके जूतों पर नज़र डालो। साफ़-सुथरे और दुरुस्त जूते व्यक्ति की सजगता और व्यवहारिकता को दिखाते हैं। महँगा होना हमेशा ज़रूरी नहीं है,पर सलीक़ा और सादगी हर पहनावे को गरिमा दे देते हैं।



हेयरस्टाइल और आँखें, मौन संवाद के माध्यम,

हमारा हेयरस्टाइल या बालों को संवारने का ढंग भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। कोई बेहद सादा और अनुशासित अंदाज़ पसंद करता है,तो कोई समय और दौर के साथ बदलते रुझानों को अपनाता है। बालों की देखभाल और व्यवस्था अक्सर इंसान की दिनचर्या और आत्म-अनुशासन की झलक देती है। इन सबमें सबसे प्रभावशाली होती हैं आँखें। आँखों में मौजूद चमक,ठहराव,विनम्रता या तीक्ष्णता किसी भी बनावटी आवरण को भेद सकती है। आँखें वह दर्पण हैं जहाँ थकान भी छिपती है,अनुभव की गहराई भी दिखती है और संवेदनशीलता भी। शब्दों से जो बात अधूरी रह जाए,आँखें उसे पूरा कर देती हैं।

और भी कई बातें: वाणी,मुद्रा और संगति,

एक संपूर्ण व्यक्तित्व केवल बाहरी सजावट से नहीं बनता। इसमें कई सूक्ष्म पहलू जुड़े होते हैं,और भी कई बातें, वाणी,मुद्रा और संगति विनम्र,स्पष्ट और संतुलित वाणी किसी भी व्यक्ति को सहज ही प्रभावशाली बना देती है। बैठने और चलने की मुद्रा , आत्मविश्वास से भरी लेकिन अक्खड़ता से मुक्त मुद्रा इंसान के भीतर के संतुलन को दर्शाती है।समय की पाबंदी और व्यवहार,दूसरों के समय का आदर करना और छोटे-बड़े सभी से समान सम्मान से पेश आना सच्चे बड़प्पन की पहचान है। भीतर की गहराई,बाहरी आवरण कितना भी आकर्षक क्यों न हो,यदि भीतर संवेदना, ईमानदारी और समझ की कमी हो, तो वह प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिकता।हमारा पहनावा, हमारे जूते, हमारा हेयरस्टाइल और हमारी आँखें,ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व की पहली तस्वीर बनाते हैं। असली स्टेटस वह है जो दिखावे से परे हो,जहाँ बाहरी सलीका भीतर की सादगी,शालीनता और आत्मविश्वास से जुड़ा हो। जब बाहर और भीतर का यह तालमेल सध जाता है, तभी पर्सनैलिटी में एक ऐसी सहज गरिमा आती है जो लोगों के मन पर स्थायी छाप छोड़ जाती है।क्या आप इस आलेख को किसी विशेष मंच या पत्रिका के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हम इसका स्वर या लंबाई उसी के अनुसार और निखार सकें?

नकली चाबी

रात के ठीक दो बजकर पैंतीस मिनट पर शहर के बाहरी इलाके में खड़े एक वीरान,अधबने कंक्रीट के ढांचे की सोलहवीं मंजिल पर एक टार्च की मद्धिम रोशनी चमकी।नीचे मुख्य द्वार पर लगे विशाल डिजिटल एलईडी बिलबोर्ड पर रंग-बिरंगे अक्षर जगमगा रहे थे 'ड्रीम वैली स्मार्ट होम्स आपका स्वर्ग,आपकी चाबी! रेरा पंजीकृत एवं शत-प्रतिशत सुरक्षित।'तभी नीचे बैठे चौकीदार के मोबाइल पर मोशन-सेंसर का लाल अलर्ट बजा। स्क्रीन पर चेतावनी उभरी 'टावर नंबर सात की सोलहवीं मंजिल पर संदेहास्पद हरकत!'

कंट्रोल रूम में सनसनी फैल गई। पिछले छह सालों से बंद पड़े इस भूतहा,बिना लिफ्ट और बिना प्लास्टर वाले कंक्रीट के जंगल में आधी रात को कौन चढ़ा था? क्या कोई लोहे के सरिए काटने वाला गिरोह घुसा था? या कोई अनहोनी होने वाली थी?सायरन बजाती हुई पुलिस की रात्रि गश्त वैन और चौकीदार टार्च चमकाते हुए अंधेरी, टूटी सीढ़ियों पर दौड़ पड़े। रोमांच और रहस्य हर कदम के साथ गहराता जा रहा था।

जब दारोगा जी हांफते हुए सोलहवीं मंजिल के उस खुले,बिना रेलिंग वाले ढांचे पर पहुंचे,तो टार्च की रोशनी में जो दृश्य दिखा, उसने वर्दी की सारी सख्ती पिघला दी।वहां न कोई चोर था,न कोई गिरोह। नंगी ईंटों के उस ठंडे फर्श पर चौंसठ साल के रिटायर्ड क्लर्क गोपाल बाबू अपनी बीमार पत्नी कमला को एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाए खड़े थे। पास में ईंट के टुकड़ों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का दीया टिमटिमा रहा था। दारोगा ने घबराकर पूछा,अरे बाबूजी! इस खंडहर में इतनी ठंड में आधी रात को क्या कर रहे हो? रेलिंग भी नहीं है,नीचे गिर जाओगे!

गोपाल बाबू ने अपनी सूखी,धंसी हुई आंखों से उस अधूरी दीवार की तरफ देखा। उनकी आवाज किसी गहरी खाई से निकलती हुई लगी।दारोगा जी...आज पूरे दस साल हो गए। कमला को आखिरी स्टेज का फेफड़ों का रोग है। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब कुछ घंटों की मेहमान है। इसने दस साल से बस एक ही जिद पकड़ रखी थी कि मरने से पहले एक बार अपने पैसे से खरीदे हुए इस 1604 नंबर फ्लैट में दीया जलाना है.। यार,तुमने कभी किसी सीधे-सादे आदमी को अपने ही खून-पसीने की कमाई से खरीदे गए खंडहर में गृह-प्रवेश करते देखा है? दस साल पहले गोपाल बाबू ने अपनी पूरी ग्रेच्युटी,पत्नी के गहने और बैंक से भारी कर्ज लेकर अड़तीस लाख रुपये इस 'स्मार्ट टाउनशिप' में लगाए थे। बिल्डर ने एचडी ब्रॉशर दिखाकर वादा किया था कि चौबीस महीने में चाबी हाथ में होगी। चौबीस महीने दस साल में बदल गए। बिल्डर ने पोर्टल पर इस कंपनी को 'दिवालिया' घोषित किया और अगले ही महीने शहर के दूसरे छोर पर पचास करोड़ का नया 'अल्ट्रा-लग्जरी प्रोजेक्ट' लॉन्च कर दिया।

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

बदलती सियासी बिसात और हिंदुत्व की अपरिहार्यता

भारतीय लोकतंत्र की सियासी व्याकरण पिछले एक दशक में जिस तेजी से बदली है,उसने दशकों पुराने राजनीतिक मिथकों को ध्वस्त कर दिया है। विशेष रूप से हिंदी पट्टी के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसकी दशा और दिशा कभी मस्जिदों की चौखट,मदरसों के गलियारों और रोजा-इफ्तार की भव्य दावतों से तय होती थी,आज एक नए वैचारिक ध्रुव पर खड़ी है। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शेष तमाम राजनीतिक दलों के नेता बहुसंख्यक समाज के धार्मिक अनुष्ठानों,तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक आयोजनों से सार्वजनिक दूरी बनाना ही अपनी प्रगतिशीलता और धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। स्थिति यह थी कि कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पाबंदियां लगाना हो या रामनवमी की शोभायात्राओं पर होने वाले उपद्रव, ऐसे तत्वों को गैर-भाजपा दलों का प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण मिलना एक सामान्य राजनीतिक परिपाटी बन चुकी थी। किंतु आज भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में एक ऐसी प्रबल वैचारिक लहर बह रही है, जिसने सत्ता और समाज के केंद्र में हिंदुत्व को स्थापित कर दिया है।


स्वदेश कुमार
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

भाजपा के राष्ट्रीय उभार के बाद यह वैचारिक परिवर्तन साकार हुआ है। इसके बावजूद विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा आज भी धर्मनिरपेक्षता के पुराने खोल में लिपटी अल्पसंख्यक-केंद्रित राजनीति का मोह नहीं छोड़ पा रहा है, जिसके कारण इस विचारधारा को जनमानस में छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा मिली। ऐसे में,जब इसी सेक्युलर राजनीति के सबसे मुखर पैरोकारों में से एक, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दर्शन करने जाने की चर्चा जोर पकड़ती है, तो इसे महज एक सामान्य धार्मिक यात्रा मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह भारतीय राजनीति में आ रहे उस गहरे वैचारिक विस्थापन का प्रतीक है,जहां अब विरोधियों को भी अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए उसी राह पर चलने को विवश होना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जिस राजनीतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं,उसकी न तो राम मंदिर निर्माण आंदोलन में कोई सकारात्मक भूमिका रही है और न ही वह इतिहास के उस अध्याय को स्वीकार करती है,जिसने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। फिर भी,यदि वे रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने का मन बना रहे हैं,तो इसका सीधा निहितार्थ यही है कि सत्ता के गलियारों तक वापसी के लिए अब उन्हें भी हिंदुत्व के प्रतीकों को स्वीकार करना अपरिहार्य लगने लगा है।



यद्यपि आज हिंदुत्व की राजनीति का सबसे प्रखर और सर्वमान्य चेहरा भाजपा बन चुकी है,लेकिन स्वाधीनता के बाद के शुरुआती दशकों में इस वैचारिक मशाल को हिंदू महासभा और स्वामी करपात्री जी महाराज की रामराज्य परिषद ने थाम रखा था। भाजपा का पूर्ववर्ती स्वरूप, भारतीय जनसंघ भी इसी वैचारिक श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी था। इन दलों ने उस दौर की प्रचलित राजनीति को सीधी चुनौती दी, जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुसंख्यक समाज के अधिकारों, उसकी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं की निरंतर उपेक्षा कर रही थी। इस धारा का मूल स्वर हमेशा से यही रहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियां लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध हैं। हालांकि तत्कालीन सत्ताधारी विमर्श ने बड़ी चतुराई से तुष्टीकरण के इस विरोध को अल्पसंख्यक विरोध के रूप में प्रचारित किया। परिणामस्वरूप, देश के बौद्धिक और राजनीतिक विमर्श में सेक्युलरवाद एक ऐसा फैशन बन गया, जहां हिंदू परंपराओं को रूढ़िवादी बताना ही आधुनिकता का पैमाना मान लिया गया।

वर्ष 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के ऐतिहासिक उभार के पीछे हिंदुत्व की इसी मुखर राजनीति की निर्णायक भूमिका रही,लेकिन विपक्षी खेमे ने इसे राजनीति की स्थायी धुरी मानने से इनकार कर दिया। तमाम तथाकथित सेक्युलर दलों को यह लगा कि यह उभार महज एक तात्कालिक उबाल है और जल्द ही राजनीति अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगी। परंतु तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ अपवादों को छोड़ दें,तो देश के अधिकांश हिस्सों में इस वैचारिक धारा ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा लीं कि विरोधियों के लिए इसे रोकना असंभव हो गया। जब विपक्ष इस आंधी को थामने में नाकाम रहा, तो उसे मजबूरी में ही सही, खुले या छिपे रूप में हिंदुत्व के प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा। इसकी सबसे स्पष्ट झलक 2017 के गुजरात और 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में देखने को मिली,जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनेऊ धारण कर मंदिर-मंदिर माथा टेकना शुरू किया। गुजरात में यह प्रयोग विफल रहा,लेकिन कर्नाटक में सत्ता की चाबी मिलने के बाद वे पुनः अपनी पुरानी वैचारिक धारा की ओर लौट पड़े। भारतीय राजनीति के इस विरोधाभास को समझने के लिए नब्बे के दशक के उस दौर का स्मरण आवश्यक है,जब मुलायम सिंह यादव पहली बार भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे,किंतु बाद में उनकी पूरी राजनीति भाजपा विरोध के इर्द-गिर्द ही सिमट गई। वर्ष 1990 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथयात्रा शुरू की, तो तत्कालीन जनता दल के क्षत्रपों विशेषकर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच आडवाणी को गिरफ्तार कर मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ लग गई। लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, तो कुछ ही समय बाद मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलाई गईं। इन घटनाओं ने देश की राजनीति को दो स्पष्ट/ध्रुवों में बांट दिया। एक ओर भाजपा हिंदुत्व के सबसे प्रखर रक्षक के रूप में उभरी, तो दूसरी ओर लालू और मुलायम हिंदुत्व विरोधी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर अपने-अपने राज्यों में लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहे। राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी

राजनीतिक मंच पर शिक्षक की सक्रियता पर शिक्षा विभाग सख्त,संकुल समन्वयक को थमाया कारण बताओ नोटिस

भाजपा के राजनीतिक आयोजन में मंच संचालन और जनप्रतिनिधियों के पक्ष में वक्तव्य देने का आरोप...24 घंटे में मांगा जवाब...संकुल समन्वयक का प्रभार छीनने और निलंबन की कार्रवाई के संकेत...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले एक शिक्षक की राजनीतिक मंच पर सक्रियता अब उनके लिए विभागीय मुश्किल का कारण बनती दिखाई दे रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड में पदस्थ शिक्षक (एलबी) एवं संकुल शैक्षिक समन्वयक सुशील मिश्रा को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षक पर एक विशेष राजनीतिक दल के बड़े आयोजन में मंच संचालन करने और सार्वजनिक मंच से संबंधित दल तथा जनप्रतिनिधियों के पक्ष में प्रशंसात्मक वक्तव्य देने का आरोप है। मामले में भाजपा सीतापुर मंडल अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सहनपुर के उपसरपंच त्रिलोचन सदावर्ती द्वारा 17 नवंबर 2026 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो और वीडियो भी संलग्न किए गए हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 17 नवंबर को शिक्षक सुशील



मिश्रा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो और वीडियो में शिक्षक एक राजनीतिक दल के आयोजन के मंच का सक्रिय संचालन करते तथा दल और जनप्रतिनिधियों के पक्ष में प्रशंसात्मक वक्तव्य देते दिखाई दे रहे हैं। विभाग ने इसे शासकीय सेवक की राजनीतिक तटस्थता और सेवा आचरण के विपरीत मानते हुए गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है।

सरकारी पद की मर्यादा पर उठे सवाल : शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-5 का हवाला देते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को नियमों का उल्लंघन बताया है। विभाग का तर्क है कि शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी सेवा की निष्पक्षता और पद की गरिमा को प्रभावित नहीं कर सकता। खास बात यह है कि संबंधित शिक्षक केवल विद्यालयीन कार्यों से ही नहीं जुड़े हैं,बल्कि संकुल शैक्षिक समन्वयक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं।

प्रभार छीनने से लेकर निलंबन तक की चेतावनी

जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक से पूछा है कि शासकीय शिक्षक और संकुल समन्वयक के महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व पर रहते हुए वे किस हैसियत से राजनीतिक मंच का संचालन और राजनीतिक वक्तव्य देने पहुंचे थे। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें संकुल समन्वयक के प्रभार से तत्काल पृथक करने के साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम-9 के तहत निलंबन एवं विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

राजनीतिक मंचों पर सरकारी सेवकों की मौजूदगी पर फिर बहस

यह मामला सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और सेवा आचरण नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। शासकीय सेवक किसी भी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक या विरोधी निजी तौर पर हो सकते हैं,लेकिन सरकारी पद पर रहते हुए उनकी सार्वजनिक भूमिका निष्पक्षता के दायरे में रहनी चाहिए। ऐसे में यदि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक शिक्षक के आचरण का मामला नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं की निष्पक्षता और प्रशासनिक मर्यादा से भी जुड़ा विषय होगा। फिलहाल शिक्षक का पक्ष सामने नहीं आया है। विभागीय नोटिस में स्पष्टीकरण के लिए 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि शिक्षक अपने बचाव में क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं और शिक्षा विभाग जांच के बाद क्या निर्णय लेता है।

गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी-शालिग्राम का कराया विवाह,छोटी दिवाली की तरह मना देवउठनी एकादशी

बाजार में रही रौनक,गन्ना 50-60 रुपए जोड़ी बिका, आतिशबाजी के साथ घरों में हुई पूजा-अर्चना,मांगलिक कार्य शुरू



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला मुख्यालय अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में शुक्रवार को देवउठनी एकादशी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। घरों में गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया गया। शाम को विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाईं। सरगुजा में देवउठनी एकादशी को छोटी दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा है। इसी के चलते शहर के बाजारों में दिवाली जैसी रौनक देखने को मिली। पर्व को लेकर सुबह से ही बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। गन्ना,फूल-माला और पूजा सामग्री की जमकर बिक्री हुई। एक दिन पहले से ही शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के किसान गन्ना लेकर बाजार पहुंचने लगे थे। गन्ना 50 से 60 रुपए जोड़ी बिका। इसके अलावा पूजा में उपयोग होने वाले फूल-माला और शकरकंद की भी लोगों ने खरीदारी की।

घरों में सजे गन्ने के मंडप,हुई आतिशबाजी : देवउठनी एकादशी पर लोगों ने दिवाली की तरह घरों की साफ-सफाई की और शाम को आंगन में आकर्षक रंगोली बनाई। इसके बाद गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया। पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने घरों के बाहर दीप जलाए। रात में बच्चों से लेकर बड़ों तक ने आतिशबाजी कर पर्व की खुशियां मनाईं। पूरे शहर में देर रात तक उत्सव का माहौल बना रहा।

देवउठनी एकादशी से शुरू हुए मांगलिक कार्य : धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी पर चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है। इसके बाद विवाह,गृह प्रवेश सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

आश्वासन पर नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल स्थगित

एक माह में मांगें पूरी नहीं हुईं तो फिर शुरू होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन



-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य मंत्री से हुई चर्चा और मिले आश्वासन के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। 18 नवंबर से शुरू हुआ आंदोलन दो दिन बाद ही स्थगित करने का निर्णय लिया गया। संघ की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रीना राजपूत ने 19 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। संघ की सरगुजा अध्यक्ष के अनुसार,आंदोलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री ने पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया था। मरीजों के हितों को देखते हुए मंत्री के निर्देश पर डेली वेजेस और संविदा कर्मचारियों को तत्काल काम पर भेज दिया गया था, ताकि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों। चर्चा के दौरान आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की ओर से गठित कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार प्रस्ताव शासन को भेजने और बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद संघ पदाधिकारियों की सहमति से आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। नर्सिंग अधिकारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे में सुधार, वेतनमान का निर्धारण, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस शामिल हैं। संघ का कहना है कि वर्ष 2018 में गठित कमेटी की अनुशंसाओं के बावजूद अब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे नाराज नर्सिंग अधिकारी आंदोलन कर रहे थे।

हालांकि संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि एक माह के भीतर ग्रेड पे,वेतनमान,नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस को लेकर आदेश जारी नहीं किए गए तो अनिश्चितकालीन आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। हड़ताल स्थगित होने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है।

कटाई के वक्त फिर बारिश की मार,आधी धान फसल खेतों में,किसानों की बढ़ी चिंता

अकवान चक्रवात से सरगुजा में बदला मौसम,शाम तक 7.4 मिमी बारिश,अक्टूबर में अर्नब से हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

खेतों में पककर तैयार धान की फसल, खलिहानों में रखी उपज और कटाई के इंतजार में बैठे किसानों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। अक्टूबर में अर्नब चक्रवात के कारण हुई बारिश से हुए नुकसान से किसान अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अब अकवान चक्रवात ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर बाद बूंदाबांदी शुरू हुई, जो शाम होते-होते तेज बारिश में बदल गई। शाम 5 बजे तक अंबिकापुर में 7.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम के इस बदलाव ने खेतों में खड़ी और कटी हुई धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरगुजा जिले में अभी 50 प्रतिशत से अधिक धान की कटाई बाकी है। कई गांवों में फसल खेतों में तैयार खड़ी है, जबकि कुछ किसानों ने कटाई के बाद धान खेतों और खलिहानों में रखा है। ऐसे समय में बारिश होने से धान के दाने



भीगने, गुणवत्ता खराब होने और उपज के दाम प्रभावित होने का खतरा है। वहीं,धान खरीदी का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में बारिश का असर किसानों की उपज को सुरक्षित रखने और खरीदी केंद्रों तक धान पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।

पिछली बारिश के नुकसान से अब तक नहीं उबरे किसान : किसानों की परेशानी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अक्टूबर में अर्नब चक्रवात के दौरान हुई बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा था। खासकर सूरजपुर जिले के बिहारपुर-चांदनी क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। प्रभावित किसानों को अब तक राहत और मुआवजे का इंतजार है। ऐसे में दोबारा बारिश ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि बीज, खाद, मजदूरी और अन्य कृषि संसाधनों पर बड़ी लागत लगाने के बाद फसल तैयार होती है। कटाई के समय बारिश होने से पूरी मेहनत और लागत पर पानी फिरने का खतरा है। ग्रामीण किसानों ने जिला प्रशासन और कृषि विभाग से प्रभावित गांवों में तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछली बारिश से हुए नुकसान के साथ वर्तमान बारिश से प्रभावित खेतों का भी आकलन किया जाए, ताकि पात्र किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।

शनिवार तक रह सकता है... चक्रवात का असर,फिर बढ़ेगी ठंड

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में करीब 10 दिन पहले बना अकवान चक्रवात अब कमजोर पड़ गया है। इसके प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ में शनिवार तक मध्यम बारिश और हवा चलने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ होने पर दो से तीन दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। इससे सरगुजा संभाग में ठंड का असर बढ़ेगा और कड़ाके की ठंड पडने की संभावना है।

खीस्त राजा पर्व के अवसर पर निकलेगी विशाल शोभायात्रा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

क्रिसमस के ठीक एक माह पूर्व मसीही समाज द्वारा मनाए जाने वाले खीस्त राजा पर्व के अवसर पर रविवार को नगर में विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा बेदाग ईश माता महागिरिजा घर नवापारा से प्रारंभ होकर सेंट जेवियर परिसर में समाप्त होगी। इसके बाद समस्त धार्मिक अनुष्ठान अंबिकापुर धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप डॉ. अंतोनिस बड़ा की अगुवाई में संपन्न होंगे। शोभायात्रा महागिरिजा घर से प्रारंभ होकर गांधी चौक,घड़ी चैक, संगम चौक,महामाया चौक,गुरुनानक चैक, गुदरी चौक,जीईएल चर्च,जोड़ा पीपल,आकाशवाणी चौक से होते हुए सेंट जेवियर प्रांगण में पहुंचेगी। इस शोभायात्रा में मसीही समाज के लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। शोभायात्रा में बाइबिल के संदेश,भजन-कीर्तन, बैंड-बाजा और झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। बच्चे,युवा और बुजुर्ग सभी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे।



लावारिस इनोवा से 70 किलो गांजा जब्ती मामले में दो महीने बाद आरोपी गिरफ्तार

फास्टैग और तकनीकी साक्ष्यों से खुला तस्करी का राज,50.19 लाख रुपये का मशरूका जब्त,ओडिशा से यूपी ले जा रहा था गांजा,हादसे के बाद कार छोड़कर हुआ था फरार

-संवाददाता-
बलरामपुर-रामानुजगंज,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश सीमा के पास लावारिस हालत में खड़ी इनोवा कार से 70 किलो से अधिक गांजा बरामद होने के मामले में करीब दो महीने बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना बसंतपुर पुलिस ने फास्टैग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गांजा तस्करी में कथित रूप से शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे और तस्करी में प्रयुक्त इनोवा कार की कुल कीमत 50 लाख 19 हजार 500 रुपये आंकी गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार,22 सितंबर 2026 को ग्राम फुलीडुमर से महुवारी जाने वाले मार्ग के किनारे एक इनोवा कार (क्रमांक MH 04 DY 9471) काफी समय से लावारिस खड़ी होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में मैकेनिक की मदद से कार का लॉक खुलवाकर तलाशी ली। इस दौरान डिक्की से भूरे टेप में लिपटे 18 पैकेट और हरे रंग की प्लास्टिक बोरी से 16 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कुल 34 पैकेटों का वजन 70.390 किलोग्राम पाया गया,जिसकी कीमत



35 लाख 19 हजार 500 रुपये बताई गई। इसके अलावा करीब 15 लाख रुपये कीमत की इनोवा कार भी जब्त की गई।

फास्टैग ने पहुंचाया आरोपी तक : कार से गांजा बरामद होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 148/2026, धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने वाहन में लगे फास्टैग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसी आधार पर अशोक कुमार यादव (43), पिता नखदू यादव,निवासी पालघर,महाराष्ट्र,हाल मुकाम मिर्जापुर एवं चंदौली,उत्तर प्रदेश की संलिप्तता सामने आई।

ओडिशा से गांजा लोड कर यूपी जा रहा था आरोपी : पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने इनोवा कार मुंबई में एक व्यक्ति से खरीदी थी, लेकिन वाहन का अपने नाम पर हस्तांतरण नहीं कराया था। कोरोना काल में दुकान बंद होने के बाद वह गांव लौट आया और ड्राइवरी करने लगा। आरोपी के कथित बयान के अनुसार, जुलाई 2026 में उसने अपने साथियों के साथ ओडिशा के सुंदरगढ़ से इनोवा में गांजा लोड किया था। इसके बाद 22 सितंबर को ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इसी दौरान वाड्रफनगर के पास एक ट्रक के पेड़ से टकराने के कारण आगे चल रहे वाहन ने अचानक ब्रेक लगाया। पीछे से आ रही इनोवा की टक्कर हो गई। हादसे के बाद पकड़े जाने के डर से आरोपी वाहन लेकर वहां से निकल गया और छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश सीमा के पास पुलिस की मौजूदगी की आशंका होने पर कच्चे रास्ते में कार खड़ी कर अपने साथियों के साथ फरार हो गया।

साथियों की तलाश जारी : करीब दो महीने तक चली विवेचना के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है,लेकिन गांजे की इतनी बड़ी खेप के परिवहन में शामिल अन्य लोगों की भूमिका अब भी जांच का विषय है। पुलिस फरार साथियों की तलाश के साथ तस्करी के नेटवर्क और गांजे के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

पैरोल पर जेल से छूटा दुष्कर्म का दोषी बंदी नहीं लौटा,फरार घोषित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

केंद्रीय जेल अंबिकापुर से पैरोल पर रिहा हुआ दुष्कर्म का दोषी बंदी निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटा। जेल प्रशासन ने उसे फरार घोषित करते हुए मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जेल प्रशासन के अनुसार,फरार बंदी विकास बड़ा (22) पिता बलराम बड़ा, ग्राम पेटला, थाना सीतापुर का निवासी है। उसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जशपुर (अतिरिक्त प्रभार एफटीसी) ने 14 सितंबर 2022 को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और मारपीट के मामले में दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई थी। उसे विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष, 10 वर्ष और तीन-तीन माह के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा मिली थी। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान था। वह केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था। मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश पर उसे 30 सितंबर 2026 को 14 दिन की अस्थायी मुक्ति पर रिहा किया गया था। नियमानुसार उसे 15 अक्टूबर 2026 को शाम 5 बजे जेल बंद होने से पहले वापस उपस्थित होना था,लेकिन वह निर्धारित समय पर नहीं लौटा। जेल प्रशासन ने उसका इंतजार किया, लेकिन बंदी की वापसी नहीं हुई। जेल नियमावली के अनुसार, छुट्टी की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर जेल बंद होने से पहले वापस नहीं आने वाले बंदी को फरार माना जाता है। इसी आधार पर जेल प्रशासन ने मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस बंदी के घर और परिजनों के साथ परिचितों के ठिकानों पर दबिश देकर उसकी तलाश कर रही है। सीतापुर पुलिस को भी सूचना दी गई है।



नगर के वरिष्ठ एवं सम्मानित नागरिक जौहरी लाल गोयल का निधन

-संवाददाता-
सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।



नगर के वरिष्ठ एवं सम्मानित नागरिक तथा गोयल परिवार के श्याम भक्त जौहरी लाल गोयल का आज 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनके निधन की खबर से नगर में शोक की लहर दौड़ गई,उनका अंतिम संस्कार स्थानीय नमदगिरी स्थित रेणिन नदी तट मुक्तिधाम में किया गया,जहां बड़ी संख्या में परिजन,रिश्तेदार, नगर के गणमान्य नागरिक एवं शुभचिंतक उपस्थित रहे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी,स्वर्गीय जौहरी लाल गोयल,संजय गोयल,राजेश गोयल (कल्लू),राम गोयल (बिगल) एवं श्याम अग्रवाल (भोलू) के पूज्य पिताश्री थे,उनके निधन पर नगर के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें।

अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलटी,7 घायल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सीतापुर थाना क्षेत्र के एनएच-43 जूना मंगारी में भारत पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से स्कार्पियो पलट गई थी,जिसमें अंबिकापुर निवासी 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों का इलाज चल रहा है। 16 नवम्बर को हुए हादसे में सीतापुर थाना पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, वाहन चालक का काम करने वाला कृष्ण कुमार निवासी लक्ष्मीपुर, अंबिकापुर 16 नवम्बर को स्कार्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 डीसी 7162 में सवार होकर प्रातः 5.30 बजे अंबिकापुर से परिवार के सदस्यों के साथ संबलपुर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम में शामिल होकर वापस घर अंबिकापुर लौटते समय जूना मंगारी में भारत पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 9572 के चालक ने तेज गति में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए रात करीब 9.30 बजे ठोकर मार दी, जिससे स्कार्पियो वाहन पलट गई। वाहन में सवार रामेश्वर प्रसाद 68 वर्ष,राजकुमारी देवी 67 वर्ष,शकुंतला देवी 70 वर्ष, तारामणी देवी 65 वर्ष, प्रिया 40 वर्ष, मिली 45 वर्ष,कृष्णा कुमार 33 वर्ष,सभी निवासी लक्ष्मीपुर घायल हो गए,जिससे कोहराम की स्थिति बन गई।

अवैध धान भंडारण पर कार्रवाई,658 क्विंटल धान जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

धान खरीदी का कार्य चल रहा है। इस दौरान अवैध धान भंडारन व खरीदी का कार्य होने की आशंका है। नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा टीम गठित की गई है।

इसी क्रम में खाद्य विभाग एवं मंडी की संयुक्त जांच दल द्वारा अंबिकापुर एवं श्रीगढ़ स्थित विभिन्न ट्रेडर्स के प्रतिष्ठानों में जांच की गई। जांच के दौरान कुल 658 क्विंटल धान जब्त किया गया। संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर खाद्य विभाग एवं मंडी की संयुक्त जांच दल द्वारा यह कार्रवाई की गई। जांच के दौरान कृष्णा ट्रेडिंग से 160 क्विंटल, महामाया ट्रेडिंग श्रीगढ़ से 158 क्विंटल, आदर्श ट्रेडिंग श्रीगढ़ से 140 क्विंटल तथा जेके ट्रेडिंग श्रीगढ़ से 200 क्विंटल धान जब्त किया गया। इस प्रकार चारों प्रतिष्ठानों से कुल 658 क्विंटल धान जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध धान के भंडारण,परिवहन एवं व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए विभागीय टीम द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।



बीमारी ने तोड़ा शरीर, कर्ज ने तोड़ी कमर...

अब मेडिकल बिलों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे शिक्षक

मेडिकल बिलों में कथित कमीशनखोरी की शिकायत से मचा हड़कंप



यादवेंद्र दुबे
जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ



- सिविल सर्जन से परीक्षण के बाद भी महीनों तक लंबित हैं कई प्रकरण
- 5 से 10 प्रतिशत कथित कमीशन मांगने का गंभीर आरोप
- बीईओ सूरजपुर में नियमविरुद्ध संलमीकरण की भी जांच की मांग



गौतम शर्मा
जिला सचिव
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ

शिक्षक संघ ने कलेक्टर से की मांग

- सभी विकासखंडों में लंबित मेडिकल बिलों की विकासखंडवार जांच हो
- कथित कमीशनखोरी की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जाए
- दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए

मेडिकल बिलों पर कथित कमीशन का खेल? बीमार शिक्षकों की पीड़ा लेकर कलेक्टर के दरबार पहुंचा शिक्षक संघ...

इलाज के लिए लिया कर्ज,अब भुगतान के लिए संघर्ष...शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

शिक्षकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति में देरी या जानबूझकर फाइलों को रोकने का खेल?

बीमार शिक्षक की मजबूरी पर भी कथित कमीशनखोरी के आरोप, शिक्षा विभाग में जांच की मांग

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गंभीर बीमारी से जूझते शिक्षक के लिए इलाज का खर्च उठाना ही किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता, कई शिक्षक अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी खर्च कर देते हैं, तो कई को उपचार के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है, ऐसे में शासन के नियमानुसार मिलने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि उनके लिए बड़ी आर्थिक राहत होती है, लेकिन सूरजपुर जिले में इसी राशि के भुगतान को लेकर सामने आई शिकायतों ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और मानवीय संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने जिले के विभिन्न विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों और आहरण-संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के स्तर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों को महीनों तक लंबित रखने का आरोप लगाया है, संघ की शिकायत में मेडिकल बिलों के निराकरण के लिए कथित तौर पर 5 से 10 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने की बात भी कही गई है,इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर में एक लिपिक की कथित नियमविरुद्ध कार्यालयीन संलग्नीकरण और संवेदनशील शाखाओं में उसकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, मामले को लेकर शिक्षक संघ ने कलेक्टर से शिकायत कर लंबित प्रकरणों की विकासखंडवार जांच, कथित कमीशनखोरी की स्वतंत्र जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

5 से 10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग-शिकायत का सबसे गंभीर पहलू चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के निराकरण के एवज में कथित तौर पर 5 से 10 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का आरोप है, शिक्षक संघ ने इस शिकायत को गंभीर बताते हुए इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, यदि जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों की आर्थिक मजबूरी के कथित शोषण का भी होगा,आखिर जिस राशि का उद्देश्य इलाज के बाद कर्मचारी को आर्थिक राहत देना है,उसी के भुगतान के लिए कथित रूप से अतिरिक्त रकम मांगने की नौबत क्यों आए? हालांकि,कमीशन मांगने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के निष्कर्ष सामने आना अभी बाकी है,ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि शिकायत को केवल औपचारिक पत्राचार तक सीमित न रखकर तथ्यों के आधार पर जांच कराई जाए।

कलेक्टर से लेकर शासन तक पहुंची शिकायत-छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर जिले के सभी बीईओ कार्यालयों और डीडीओ स्तर पर लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों की विकासखंडवार जांच कराने की मांग की है, संघ ने यह भी मांग रखी है कि प्रत्येक लंबित प्रकरण में यह पता लगाया जाए कि फाइल किस स्तर पर और कितने समय से रुकी हुई है। देरी के कारणों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए, कथित कमीशन मांगने की शिकायत की स्वतंत्र जांच हो तथा आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए,शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजे जाने की बात कही गई है।

बीमारी से जूझता शिक्षक,दफ्तरों में अटकी फाइलें

संघ के जिला सचिव गौतम शर्मा का कहना है कि गंभीर और लंबी बीमारियों से पीड़ित शिक्षक इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी तक खर्च कर देते हैं, कई कर्मचारी आर्थिक मजबूरी में कर्ज लेकर उपचार कराते हैं,उन्हें उम्मीद रहती है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन से मिलने वाली राशि से कर्ज का बोझ कुछ कम होगा,लेकिन संघ का आरोप है कि सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कई चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण बीईओ कार्यालयों और डीडीओ स्तर पर महीनों तक लंबित पड़े रहते हैं। नतीजतन, जिन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता की सबसे अधिक जरूरत है, उन्हें अपनी ही पात्र राशि के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,यहां सवाल केवल फाइलों के लंबित रहने का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की संवेदनशीलता का भी है,जिसमें गंभीर बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे कर्मचारी को इलाज के बाद भी आर्थिक राहत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, यदि दस्तावेजों में कोई कमी है तो उसकी जानकारी समय पर क्यों नहीं दी जाती? और यदि प्रकरण पूर्ण हैं तो भुगतान में देरी की वजह क्या है?

बीईओ कार्यालय सूरजपुर में संलग्न लिपिक की भूमिका पर सवाल

शिक्षक संघ ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर में एक लिपिक की कथित नियमविरुद्ध कार्यालयीन संलग्नता को लेकर भी आपत्ति जताई है,संघ का कहना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेंशन जैसे संवेदनशील कार्यों में संबंधित लिपिक की भूमिका की जांच होनी चाहिए,संघ ने कार्यालय में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने, संबंधित फाइलों के आवागमन, नोटशीट,आदेश और अन्य अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है, यह भी जरूरी बताया गया है कि संलग्नीकरण से संबंधित आदेश और नियमों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि संबंधित कर्मचारी को किस आधार पर और किन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है,इस मांग के बाद अब प्रशासनिक जांच में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्यालयीन व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित हो रही है या नहीं और लंबित प्रकरणों में किसी स्तर पर अनावश्यक हस्तक्षेप अथवा देरी हुई है।

मेडिकल बिल कर्मचारी का अधिकार, किसी अधिकारी की कृपा नहीं

शिक्षक संघ का कहना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति पात्र कर्मचारी का शासन द्वारा निर्धारित अधिकार है,न कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की व्यक्तिगत कृपा,ऐसे में भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह होनी चाहिए, अब जिला प्रशासन के सामने कई अहम सवाल हैं–जिले में कितने मेडिकल बिल लंबित हैं? कौन-से प्रकरण कितने समय से रुके हुए हैं? क्या सिविल सर्जन कार्यालय से परीक्षण के बाद भी फाइलें अनावश्यक रूप से रोकी जा रही हैं? कथित कमीशन मांगने की शिकायत में कितनी सच्चाई है? और बीईओ कार्यालय सूरजपुर में संलग्नीकरण की व्यवस्था किन नियमों के तहत की गई है? इन सवालों का जवाब केवल जांच और अभिलेखों की पड़ताल से ही सामने आ सकता है। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराए और पात्र शिक्षकों को उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान समय पर सुनिश्चित करे, बीमारी से जूझ रहे शिक्षक को अपने इलाज और परिवार की चिंता करनी चाहिए,या अपनी ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने चाहिए? अब इस सवाल का जवाब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को देना होगा।

मदिरा दुकान की बिक्री राशि में 7.59 लाख की हेराफेरी,सुपरवाइजर गिरफ्तार

बैंक में जमा होनी थी बिक्री की रकम, सत्यापन में सामने आई गड़बड़ी

लंबे समय से चल रहा था फरार, पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी

-संवाददाता-

वाड्रफनगर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कंपोजिट मदिरा दुकान वाड्रफनगर की बिक्री राशि में 7 लाख 59 हजार 720 रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दुकान के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। ऑडिट के दौरान बिक्री और बैंक में जमा रकम के बीच बड़ा अंतर सामने आने के बाद मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। अब उससे रकम की हेराफेरी और संभावित संलिप्तता को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार,3 जुलाई 2026 को आबकारी उपनिरीक्षक अभिषेक कुमार राजवाड़े ने चौकी वाड्रफनगर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 1 मई से 11 जून 2026 तक कंपोजिट मदिरा दुकान का भौतिक सत्यापन एवं ऑडिट किया गया था। इस दौरान दुकान की बिक्री का हिसाब और प्रतिदिन बैंक में जमा की गई राशि का मिलान करने पर 7,59,720 रुपये कम पाए गए। जांच में दुकान के सुपरवाइजर लाल बिहारी यादव की जिम्मेदारी सामने आई। वह प्रतिदिन की बिक्री का स्टॉक रजिस्टर संधारित करने और बिक्री की राशि कैश कलेक्शन एजेंसी को सौंपने के लिए जिम्मेदार था। आरोप है कि उसने बिक्री की रकम निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा नहीं



कराई,जिससे शासन के राजस्व को नुकसान पहुंचा। सत्यापन के बाद आरोपी बिना सूचना दिए दुकान से अनुपस्थित हो गया था। अपराध दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। मामले में चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 105/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं 316(5) में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। पुलिस ने बिक्री पंजी और बैंक विवरण सहित अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपी की तलाश तेज की। आखिरकार 19 नवंबर 2026 को पुलिस ने लाल बिहारी यादव (26), पिता रामनाथ यादव, निवासी ग्राम कुण्डपान,थाना बभनी,जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश),हाल मुकाम ग्राम प्रेमनगर,थाना बसंतपुर,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय वाड्रफनगर में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस अब उससे कथित हेराफेरी की रकम, उसके उपयोग और इस मामले में अन्य लोगों की संभावित भूमिका के संबंध में पूछताछ कर रही है।

पीडब्ल्यूडी सचिव का औचक निरीक्षण : अमानक भवन निर्माण पर उप अभियंता निलंबित,सड़कों की धीमी गति पर जताई नाराजगी

जशपुर दौरे पर सख्त दिखे पीडब्ल्यूडी सचिव मुकेश बंसल, बगीचा पॉलिटेक्निक भवन में अनियमितता पर उप अभियंता सस्पेंड; समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश

-संवाददाता-

जशपुरनगर,20 नवम्बर 2026। (घटती-घटना)।

लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज जशपुर जिले के प्रवास के दौरान जशपुर और पत्थलगांव संभाग में चल रहे सड़क व भवन निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता और धीमी रफ्तार देख सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई और बगीचा में निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के अमानक कार्य पर उप अभियंता श्री रमेश प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। सचिव के निर्देश पर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय निर्धारित किया गया है।

प्रमुख सड़कों की समीक्षा और समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश : निरीक्षण के दौरान श्री बंसल ने जिले की तीन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की गहन समीक्षा की और अधिकारियों व ठेकेदारों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए काम में तेजी लाने की हिदायत दी:

लुडेग-तपकरा-लवाकेरा मार्ग (41 किमी): केंद्रीय सड़क निधि के तहत बन रहे इस स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण कार्य, निर्माण एजेंसी की



प्रयोगशाला और डामर प्लांट का जायजा लेकर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा।

जशपुर-सन्ना मार्ग (17.60 किमी): 13 करोड़ 56 लाख 88 हजार रुपये की लागत से स्वीकृत इस सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

आस्ता-कुसमी मार्ग (28 किमी): 35 करोड़ 86 लाख 99 हजार रुपये की लागत वाले इस मार्ग के उन्नयन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की सख्त हिदायत दी।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद : समीक्षा बैठक में सचिव ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करने को कहा। इस निरीक्षण के दौरान प्रमुख अभियंता श्री व्ही.के. भतपहरी,सरगुजा परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री के.पी. संत,अंबिकापुर मंडल के अधीक्षण अभियंता श्री आर.एस. तोमर,कार्यपालन अभियंता (पत्थलगांव) श्री ए.डी. बंजारा और कार्यपालन अभियंता (जशपुर) श्री क्षीरसागर सेठ मौजूद रहे।

अब सूरजपुर के हुनरमंद बनेंगे जिले की तरक्की के भागीदार

कलेक्टर रेना जमील ने शुरू किया 'कौशल दान अभियान'

किसी के पास शिक्षा का ज्ञान तो किसी के पास कला,खेल,तकनीक और व्यवसाय का अनुभव, अब अपनी प्रतिभा दूसरों को सिखाकर समाज के विकास में दे सकेंगे योगदान

जनभागीदारी से कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा,उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को मिलेगा 'महीने का स्वयंसेवक' सम्मान

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। किसी व्यक्ति के पास वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है, कोई संगीत और नृत्य की बारीकियों में पारंगत है, तो कोई खेल, कंप्यूटर, तकनीक, कृषि अथवा व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष दक्षता रखता है, लेकिन अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभा और अनुभव सीमित दायरे में ही रह जाते हैं, यदि यही हुनर जरूरतमंदों,युवाओं और नई चीजें सीखने के इच्छुक लोगों तक पहुंच जाए तो समाज में कौशल विकास की एक नई व्यवस्था खड़ी हो सकती है,इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में सूरजपुर जिला प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए 'कौशल दान अभियान' की शुरुआत की है। कलेक्टर रेना जमील के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जिले के हुनरमंद नागरिकों के ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को समाज के व्यापक हित से जोड़ना है, इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले नागरिक स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देकर दूसरे लोगों को प्रशिक्षित कर सकेंगे, यह अभियान केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य,खेल,कला,संगीत,नृत्य, कंप्यूटर,तकनीकी कार्य,कृषि और व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को एक साझा मंच पर लाने का प्रयास करेगा,जिला प्रशासन की इस पहल के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि समाज के विकास में योगदान देने के लिए केवल आर्थिक संसाधन ही जरूरी नहीं हैं,बल्कि किसी व्यक्ति का ज्ञान,अनुभव और हुनर भी समाज की बड़ी पूंजी हो सकता है,जरूरत है तो केवल उस हुनर को साझा करने की इच्छाशक्ति की।

हुनर को व्यक्तिगत उपलब्धि से निकालकर सामाजिक उपयोग से जोड़ने की पहल

सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति की विशेषज्ञता उसके अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रहती है,कोई शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने में दक्ष होता है,कोई कलाकार संगीत या नृत्य की शिक्षा दे सकता है,कोई खिलाड़ी युवाओं को खेल का प्रशिक्षण दे सकता है,तो कोई तकनीकी विशेषज्ञ कंप्यूटर और डिजिटल कार्यों की जानकारी साझा कर सकता है,'कौशल दान अभियान' इन सभी प्रतिभाओं को समाज के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में एक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, इसके माध्यम से इच्छुक नागरिक अपनी विशेषज्ञता और उपलब्ध समय के अनुसार स्वैच्छिक सेवाएं दे सकेंगे, इससे एक ओर अनुभवी लोगों का ज्ञान दूसरों तक पहुंचेगा, वहीं दूसरी ओर सीखने के इच्छुक नागरिकों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा, इस पहल की विशेषता यह है कि इसमें केवल पेशेवर विशेषज्ञ ही नहीं,बल्कि अपने अनुभव और व्यावहारिक दक्षता के आधार पर किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले नागरिक भी योगदान दे सकते हैं।

शिक्षा से लेकर खेल और तकनीक तक,हर क्षेत्र के हुनरमंदों के लिए अवसर,अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन ने विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष नागरिकों को स्वयंसेवक के रूप में जुड़ने का अवसर दिया है...

- **शिक्षा एवं प्रशिक्षण :** शिक्षण कार्य में अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों और जरूरतमंदों को विषय संबंधी मार्गदर्शन तथा अध्ययन में सहयोग दे सकते हैं।
- **कला एवं संस्कृति :** संगीत,गायन,नृत्य और अन्य कलात्मक विधाओं में दक्ष नागरिक अपनी प्रतिभा नई पीढ़ी के साथ साझा कर सकते हैं।
- **खेल एवं फिटनेस :** विभिन्न खेलों में अनुभव रखने वाले खिलाड़ी और फिटनेस के क्षेत्र में दक्ष व्यक्ति युवाओं को मार्गदर्शन दे सकते हैं।
- **कंप्यूटर एवं तकनीक :** कंप्यूटर,तकनीकी कार्यों और डिजिटल दक्षता रखने वाले नागरिक इच्छुक लोगों को नई तकनीक सीखने में सहयोग कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य :** स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले नागरिक अपनी निर्धारित योग्यता एवं विशेषज्ञता के अनुरूप जागरूकता और मार्गदर्शन संबंधी सेवाएं दे सकते हैं।
- **कृषि एवं व्यवसाय :** कृषि,उद्यमिता और व्यवसाय के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग अपनी व्यावहारिक जानकारी साझा कर दूसरों की क्षमता विकसित करने में योगदान दे सकते हैं, इस प्रकार अभियान के माध्यम से जिले में उपलब्ध अलग-अलग प्रकार की प्रतिभाओं को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

युवाओं के लिए साबित हो सकता है सीखने और आगे बढ़ने का अवसर

जिले में ऐसे अनेक युवा हैं,जो कुछ नया सीखना चाहते हैं,लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं हो पाते। कई बार संसाधनों की कमी के कारण प्रतिभाशाली युवा अपनी रुचि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते,ऐसी परिस्थितियों में अनुभवी नागरिकों का मार्गदर्शन उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है,यदि किसी युवा को अपने ही क्षेत्र में किसी अनुभवी शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार, तकनीकी विशेषज्ञ या व्यवसायी से सीखने का अवसर मिलता है तो उसके कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, 'कौशल दान अभियान' के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनुभवों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की संभावना बनेगी,इससे जिले की प्रतिभाओं को जिले के भीतर ही सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिल सकता है।



जनभागीदारी से बनेगा ज्ञान और अनुभव साझा करने का मंच

जिला प्रशासन की इस पहल का महत्वपूर्ण पक्ष जनभागीदारी है,इसमें सरकार की भूमिका केवल योजना शुरू करने तक सीमित नहीं है,बल्कि नागरिकों को अपने स्तर पर समाज के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित करना भी है,समाज में ऐसे अनेक लोग हैं,जिनके पास वर्षों का अनुभव और विशेष दक्षता है,यदि वे अपने समय का कुछ हिस्सा दूसरों को सिखाने में लगाते हैं तो इससे सामाजिक सहयोग की नई परंपरा विकसित हो सकती है,अभियान का उद्देश्य भी यही है कि जिले के मानवीय संसाधनों और स्थानीय प्रतिभाओं का उपयोग केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं,बल्कि सामुदायिक विकास के लिए किया जाए, इससे सामाजिक उत्तरदायित्व,आपसी सहयोग और स्वैच्छिक सेवा की भावना को मजबूती मिल सकती है।

उत्कृष्ट काम करने वाले स्वयंसेवकों को मिलेगा सम्मान

जिला प्रशासन ने अभियान से जुड़ने वाले स्वयंसेवकों का उत्साह बढ़ाने के लिए सम्मान की व्यवस्था भी की है,इसके अंतर्गत प्रतिमाह उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्वयंसेवक को 'महीने का स्वयंसेवक' के रूप में सम्मानित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों को जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा,इस व्यवस्था का उद्देश्य उन नागरिकों के योगदान को पहचान देना है, जो अपने निजी समय और अनुभव का उपयोग समाज के दूसरे लोगों के कौशल विकास में करेंगे। इससे अन्य नागरिकों को भी अभियान से जुड़ने की प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।

महज दो मिनट में ऑनलाइन पंजीयन, घर बैठे जुड़ सकते हैं अभियान से- 'कौशल दान अभियान' में शामिल होने के इच्छुक नागरिकों के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन के अनुसार पंजीयन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक रखी गई है,जिसे लगभग दो मिनट में पूरा किया जा सकता है,इच्छुक नागरिक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से स्वयंसेवक के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं, इसमें वे अपनी रुचि, विशेषज्ञता और उपलब्ध समय के अनुरूप अभियान से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

शिक्षकों,कलाकारों,खिलाड़ियों और विशेषज्ञों से आगे आने की अपील- जिला प्रशासन ने जिले के शिक्षकों,कलाकारों, खिलाड़ियों,तकनीकी विशेषज्ञों,उद्यमियों,कृषकों और विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में अभियान से जुड़ने की अपील की है,प्रशासन की मंशा है कि जिले में उपलब्ध प्रतिभाओं को एक साझा मंच मिले और उनके अनुभव का लाभ समाज के उन लोगों तक पहुंचे, जो कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपनी क्षमता विकसित करने के इच्छुक हैं।

अभियान की सफलता जनभागीदारी और क्रियान्वयन पर निर्भर

'कौशल दान अभियान' की अवधारणा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने हुनरमंद नागरिक इससे जुड़ते हैं और उनके कौशल का लाभ जरूरतमंदों तक किस प्रकार पहुंचाया जाता है,यदि स्वयंसेवकों की विशेषज्ञता के अनुरूप प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के अवसर विकसित किए जाते हैं, सीखने के इच्छुक लोगों को उनसे जोड़ा जाता है और गतिविधियों का नियमित संचालन सुनिश्चित होता है तो यह पहल जिले में कौशल विकास का प्रभावी माध्यम बन सकती है, सूरजपुर में शुरू की गई यह पहल एक सकारात्मक संदेश देती है कि जिले के विकास के लिए केवल सरकारी योजनाओं और बजट पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है,समाज के भीतर मौजूद ज्ञान, अनुभव और प्रतिभा को भी विकास की ताकत बनाया जा सकता है,किसी का हुनर किसी दूसरे के भविष्य की राह आसान कर सकता है। यही सोच 'कौशल दान अभियान' की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अब जरूरत है कि सूरजपुर के हुनरमंद नागरिक आगे आएं और अपने ज्ञान को समाज की साझा पूंजी बनाएं।

होटलों और मिठाई दुकानों में खाद्य सुरक्षा विभाग की दबिश,खुले सांभर और बासी मिठाइयां मौके पर कराईं नष्ट

'सुरक्षित आहार हमारा अधिकार' अभियान के तहत एक दर्जन होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों का निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए गए





-संवाददाता-

सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने 'सुरक्षित आहार हमारा अधिकार' अभियान के तहत होटल,ढाबा, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकानों के खिलाफ निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है, इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में करीब एक दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, इस दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई भी की गई। निरीक्षण के दौरान खुले एवं बिना ढके रखे सांभर तथा पुराने और बासी मिठाइयां पाई गईं, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इन्हें उपभोग के लिए अनुपयुक्त मानते हुए मौके पर ही नष्ट कराया, इसके साथ ही विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए, ताकि उनकी गुणवत्ता और मानकों की जांच की जा सके,यह निरीक्षण नियंत्रक के निर्देशानुसार कलेक्टर सुश्री रेना जमील,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रशांत सिंह तथा अभिहित अधिकारी पुष्पराज चौहान के मार्गदर्शन में किया गया, कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामप्रकाश जायसवाल एवं दीपा साहू शामिल रहे।

खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने की जरूरत

अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा खाद्य कारोबारियों को निर्धारित स्वच्छता मानकों के प्रति जागरूक करना है, खुले में खाद्य पदार्थ रखना,पुराने एवं बासी खाद्य पदार्थों की बिक्री और साफ-सफाई में लापरवाही उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है,खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में इस तरह का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखा जा रहा है,खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

15 महीने से सोलर प्लांट ऑपरेटरों को नहीं मिला मानदेय, आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी

चांदनी बिहारपुर के पहाड़ी अंचल के करीब दो दर्जन गांवों में सोलर प्लांट के संचालन पर उठे सवाल,बकाया भुगतान को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई गुहार







-संवाददाता-

सूरजपुर/चांदनी बिहारपुर 20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड अंतर्गत चांदनी बिहारपुर के पहाड़ी अंचल में बिजली की समस्या दूर करने के उद्देश्य से क्रेडा विभाग द्वारा करीब दो दर्जन गांवों में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं, इन सोलर प्लांटों के माध्यम से ग्रामीणों को बिजली सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्लांट के नियमित संचालन के लिए विभाग द्वारा ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई थी,लेकिन विभागीय व्यवस्था की विडंबना देखिए कि गांवों में सोलर प्लांट को चालू और बंद करने की जिम्मेदारी संभालने वाले ऑपरेटरों को पिछले 15 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है,लंबे समय से मेहनताना नहीं मिलने के कारण ऑपरेटर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं।

हर महीने मिलता था भुगतान, अब 15 महीने से इंतजार- जानकारी के अनुसार,क्रेडा विभाग द्वारा पहाड़ी एवं दूरस्थ अंचल के गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाए गए थे,इन प्लांटों के संचालन, नियमित रूप से चालू-बंद करने और बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर ऑपरेटर रखे गए थे, शुरुआत में ऑपरेटरों को प्रत्येक महीने उनके कार्य के एवज में निर्धारित मजदूरी का भुगतान किया जाता था, इससे वे नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन पिछले 15 महीने से भुगतान नहीं होने के कारण उनके सामने परिवार का भरण-पोषण और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने की समस्या खड़ी हो गई है।

बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए रखे गए थे ऑपरेटर- ग्रामीणों का कहना है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र का पहाड़ी अंचल होने के कारण कई गांव आज भी बिजली की नियमित सुविधा के लिए सोलर पावर प्लांट पर निर्भर हैं, इसी समस्या को देखते हुए क्रेडा विभाग द्वारा गांवों में सोलर प्लांट स्थापित कर ऑपरेटरों की व्यवस्था की गई थी, ताकि समय पर प्लांट चालू और बंद हो तथा ग्रामीणों को बिजली मिलती रहे, लेकिन जब ऑपरेटरों को ही लंबे समय से मानदेय नहीं मिल रहा है तो ऐसे में व्यवस्था का नियमित संचालन भी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है, ग्रामीणों का कहना है कि योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार विभाग को ऑपरेटरों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

योजना का लाभ दिलाने के बजाय ऑपरेटरों की परेशानी बढ़ी- शासन की मंशा थी कि पहाड़ी अंचल के दूरस्थ गांवों में सोलर बिजली के माध्यम से लोगों को राहत मिले और ग्रामीणों को अंधेरे में रहने की मजबूरी से छुटकारा मिल सके, इसके लिए लाखों रुपये खर्च कर सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए तथा उनके संचालन के लिए ऑपरेटर भी रखे गए, लेकिन 15 महीने से मानदेय नहीं मिलने का मामला विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है,एक ओर ऑपरेटर अपनी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भुगतान के इंतजार में हैं,वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को भी सोलर बिजली व्यवस्था के सुचारू संचालन की चिंता सता रही है।

कलेक्टर से जांच कर बकाया भुगतान कराने की मांग...

इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने सूरजपुर कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की है,ग्रामीणों का कहना है कि क्रेडा विभाग द्वारा नियुक्त ऑपरेटरों के पिछले 15 महीनों के बकाया मानदेय की जांच कर तत्काल भुगतान कराया जाए। साथ ही सोलर पावर प्लांटों की वर्तमान स्थिति की भी गांववार जांच कराई जाए,ताकि यह पता चल सके कि कितने प्लांट नियमित रूप से संचालित हैं और कितने बंद पड़े हैं,ग्रामीणों ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लापरवाही पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए,जिससे पहाड़ी अंचल के गांवों में सोलर बिजली व्यवस्था सुचारू हो सके और ऑपरेटरों को भी उनके कार्य का मेहनताना समय पर मिल सके।



धन्यवाद सीईओ चंद्राकर जी! बर्खास्त कर्मचारी को चार साल बाद फिर मिली 'संजीवनी',बीमा घोटाले के आरोपों और पुरानी जांच पर उठा सवाल

पहले जिला प्रशासन की जांच में दोषी,फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति की कार्रवाई...अब नवंबर 2026 में जगदीश कुशवाहा की कथित वापसी! बहाली का आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं?

- पहले दोषी ठहराया, फिर सेवा से हटाया...अब चार साल बाद बहाली! 35.78 लाख के मामले में सीईओ चंद्राकर पर सवाल
- 35.78 लाख के फसल बीमा प्रकरण में बड़ा उलटफेर! कार्रवाई के बाद अब जगदीश कुशवाहा की बैंक में वापसी
- घोटाले की जांच,एफआईआर और सेवा समाप्ति भी बेअसर! आखिर किस आधार पर हुई जगदीश कुशवाहा की बहाली...
- किसानों की बीमा राशि का हिसाब अधूरा,कर्मचारी की बहाली पूरी! सहकारी बैंक में किसका चल रहा है खेल?
- जांच में दोषी,नौकरी से बर्खास्त...फिर किसकी मेहरबानी से मिली 'री-एंट्री' ?
- पुरानी जांच और कार्रवाई को पीछे छोड़ बहाली का रास्ता! सीईओ चंद्राकर के फैसले पर उठे गंभीर सवाल
- घोटाले की जवाबदेही पर सन्नाटा,बर्खास्त कर्मचारी की वापसी पर तेजी! सहकारिता विभाग में क्या पक रही खिचड़ी...
- दैनिक घटती-घटना ने 9 मार्च, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को लगातार उठाए थे सवाल
- खबरें थमते ही कथित तौर पर खुल गया वापसी का रास्ता, बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल


सहकारी बैंक में 'संरक्षण' का संदेह?


भाग-1 35.78 लाख के फसल बीमा प्रकरण की पूरी कहानी ऐसे हुआ खुलासा, जांच, FIR और कार्रवाई!
जांच में दोषी,एफआईआर और सेवा समाप्ति के बाद फिर क्यों खुला फसल बीमा घोटाले का पिटारा?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सहकारिता विभाग और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में यदि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाए, उसके विरुद्ध विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय की जाए, मामला पुलिस की एफआईआर तक पहुंचे और फिर वर्षों बाद उसी कर्मचारी की दोबारा बैंक सेवा में वापसी हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे,सवाल केवल एक कर्मचारी की बहाली का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जिसमें पहले जांच और कार्रवाई होती है,फिर उसी प्रकरण में दोबारा ऐसी कवायद शुरू होती है, जिसके बाद सेवा से पृथक कर्मचारी की वापसी की चर्चा सामने आने लगती है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से जुड़े लगभग 35.78 लाख रुपये के फसल बीमा प्रकरण में अब ऐसा ही घटनाक्रम चर्चा में है, इस मामले में पहले जांच दल ने अनियमितता के लिए कर्मचारियों की जवाबदेही तय की थी,बैंक के आदेश के अनुसार तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा सहित संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी,पुलिस में एफआईआर दर्ज होने और विभागीय प्रक्रिया के बाद जगदीश प्रसाद कुशवाहा की सेवा समाप्त किए जाने का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन अब नवंबर 2026 में विभागीय सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर के स्तर से जगदीश प्रसाद कुशवाहा को फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया है, सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि इस बहाली से संबंधित आदेश को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है,विभागीय सूत्रों का दावा है कि आदेश कार्यालयीन स्तर पर मौजूद है, लेकिन उसे सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया है,हालांकि बैंक प्रबंधन की ओर से इस कथित बहाली और आदेश की स्थिति पर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना अभी बाकी है,ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाता है कि यदि बहाली नियमों के तहत हुई है तो उसका आदेश सार्वजनिक करने में आखिर परेशानी क्या है?

सहकारिता विभाग में आखिर कौन-सी खिचड़ी पक रही है?- सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक किसानों, समितियों तथा आम खाताधारकों से सीधे जुड़े संस्थान हैं,यहां कर्मचारियों की नियुक्ति,सेवा समाप्ति और बहाली जैसे फैसले केवल कार्यालयीन औपचारिकताएं नहीं होते,बल्कि संस्था की विश्वसनीयता से भी जुड़े होते हैं,जिस कर्मचारी की सेवा जांच के बाद समाप्त की गई हो, उसकी दोबारा बहाली का निर्णय और भी अधिक पारदर्शी होना चाहिए, पुराने जांच प्रतिवेदन को सामने रखकर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उस समय कौन-से तथ्य मिले थे और अब कौन-से नए तथ्य सामने आए,जिनके आधार पर बहाली की स्थिति बनी, यदि पुराने जांच निष्कर्षों में कोई बदलाव हुआ है,तो उसका कारण भी बताया जाना चाहिए। आखिर चार साल तक सेवा से बाहर रहने के बाद अचानक बहाली की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या इस दौरान कोई अपील लंबित थी? क्या किसी न्यायिक आदेश का पालन किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब के बिना पूरा मामला संदेह के घेरे में रहेगा।

पहले जांच में दोषी, फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति- 35.78 लाख रुपये का फसल बीमा प्रकरण कोई नया या सामान्य मामला नहीं है, उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 2019-20 में किसानों की फसल बीमा राशि के कथित अनियमित आहरण का मामला सामने आया था, इस प्रकरण में जिला प्रशासन की ओर से जांच दल गठित किया गया था,जांच के बाद लगभग 35.78 लाख रुपये की राशि से जुड़ी अनियमितता का उल्लेख किया गया और संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय किए जाने की बात सामने आई,इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के आदेश क्रमांक स्थापना/2023-24/383, दिनांक 5 जून 2023 में जांच दल की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था,आदेश में तत्कालीन शाखा प्रबंधक जगदीश प्रसाद कुशवाहा, लिपिक सूबेदार सिंह, संस्था प्रबंधक राम कुमार सिंह तथा भृत्य सुनील यादव का उल्लेख है,दस्तावेज के अनुसार संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन और पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई गई थी,इसी प्रकरण में थाना झिलमिली में एफआईआर दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई थी,उपलब्ध समाचार सामग्री में अपराध क्रमांक 117/21 का उल्लेख किया गया था,संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की खबरें भी प्रकाशित हुई थीं,इसके बाद बैंक की विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ी और 5 जून 2023 के आदेश के अनुसार जगदीश प्रसाद कुशवाहा की सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया, आदेश में यह भी उल्लेख था कि संबंधित राशि की वसूली के लिए पृथक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, यानी मामला केवल आरोप लगने तक सीमित नहीं था, जिला प्रशासन की जांच,बैंक की विभागीय कार्रवाई और पुलिस में दर्ज अपराध-इन सभी स्तरों से गुजरने के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई हुई थी,ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस कर्मचारी की सेवा समाप्त की गई थी,उसकी वापसी का आधार क्या है? क्या पुरानी जांच के निष्कर्ष बदल गए हैं? क्या कोई नया दस्तावेज सामने आया है? क्या किसी सक्षम प्राधिकारी ने पूर्व आदेश को निरस्त किया है? या फिर किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बहाली की गई है? इन सवालों का जवाब बैंक प्रबंधन को स्पष्ट रूप से देना चाहिए।

23 जनवरी 2026 के आदेश को बहाली का आधार कैसे बनाया गया?- इस पूरे मामले में 23 जनवरी 2026 को संयुक्त पंजीयक,सहकारी संस्थाएं, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर द्वारा पारित आदेश भी महत्वपूर्ण है,यह आदेश प्रकरण क्रमांक 17/55(2)/2023 से संबंधित है, जिसमें जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने बैंक के 5 जून 2023 के सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी थी, उपलब्ध आदेश के अनुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और दस्तावेजों तथा तर्कों पर विचार करने के बाद जिला सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1982 के प्रावधानों के अनुरूप कर्मचारी को अपने बचाव का समुचित एवं पर्याप्त अवसर देकर विधिवत कार्रवाई करने की बात कही गई थी,यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है,उपलब्ध 23 जनवरी 2026 के आदेश को सीधे बहाली का आदेश मानना उचित नहीं होगा,उसमें निर्धारित प्रक्रिया के पालन और कर्मचारी को बचाव का अवसर देने की बात दर्ज है,इसलिए यदि इसी आदेश के अनुपालन में बैंक प्रबंधन ने आगे कोई कार्रवाई की है,तो उसे यह बताना चाहिए कि किस प्रक्रिया के तहत,किस अधिकारी के अनुमोदन से और किन दस्तावेजों के आधार पर बहाली का निर्णय लिया गया, क्या कर्मचारी को केवल अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया? क्या उसके बाद विधिवत विभागीय सुनवाई हुई? क्या नई जांच रिपोर्ट तैयार हुई? क्या सक्षम प्राधिकारी ने सेवा समाप्ति के पुराने आदेश पर पुनर्विचार किया? क्या बहाली का कोई अलग आदेश जारी किया गया? और यदि आदेश जारी हुआ है तो उसकी प्रति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इन सवालों के जवाब के बिना कथित बहाली की पूरी प्रक्रिया संदेह और अस्पष्टता के घेरे में बनी रहेगी।

खबरें थमते ही क्या बदल गया पूरा घटनाक्रम?- दैनिक घटती-घटना द्वारा मार्च और अगस्त में लगातार मामला उठाए जाने के बाद यह प्रकरण कुछ समय के लिए सार्वजनिक चर्चा से दूर हो गया था,अब विभागीय सूत्रों के हवाले से नवंबर में बहाली की जानकारी सामने आने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि सेवा समाप्त किए गए कर्मचारी की वापसी का रास्ता खुल गया? क्या नई जांच पूरी हो गई थी? क्या जांच में पुराने निष्कर्षों से अलग कोई तथ्य सामने आया? क्या बैंक के सक्षम प्राधिकारी ने पुरानी कार्रवाई को निरस्त किया? क्या संयुक्त पंजीयक के आदेश के अनुपालन में कोई नया विभागीय आदेश जारी किया गया? यदि हां,तो उस आदेश की तारीख, क्रमांक और कानूनी आधार क्या है? यदि बहाली पूरी तरह नियमों के तहत हुई है तो बैंक प्रबंधन को उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। किसी कर्मचारी को न्यायिक या विभागीय प्रक्रिया के तहत राहत मिलती है तो वह उसका अधिकार हो सकता है,लेकिन ऐसी राहत का आधार पारदर्शी होना चाहिए,विशेषकर तब,जब मामला किसानों की फसल बीमा राशि से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितता का हो।

35.78 लाख रुपये का हिसाब कौन देगा?-इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल किसी कर्मचारी की नौकरी या बहाली से भी बड़ा है, वह सवाल है किसानों की फसल बीमा राशि का। उपलब्ध दस्तावेजों में 35.78 लाख रुपये की राशि का उल्लेख है,ऐसे में बैंक प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस राशि का वास्तविक हिसाब क्या है? कितने किसानों की फसल बीमा राशि प्रभावित हुई थी? किसानों के खातों से कथित रूप से कितनी राशि निकाली गई? कुल 35.78 लाख रुपये में से कितनी राशि की वसूली हुई? कितनी राशि अब भी शेष है? क्या प्रभावित किसानों को उनकी राशि वापस की गई? यदि वसूली हुई है तो उसका विवरण क्या है? और यदि राशि की वसूली अब तक नहीं हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि विभागीय कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय अनियमितता के लिए जिम्मेदारी तय करना था,तो सेवा में वापसी की प्रक्रिया के साथ-साथ किसानों की राशि और वसूली का प्रश्न भी उतनी ही गंभीरता से सामने आना चाहिए,ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्मचारी की सेवा बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाए,लेकिन जिस राशि को लेकर पूरा मामला खड़ा हुआ था,उसका हिसाब वर्षों बाद भी स्पष्ट न हो, किसानों की राशि का हिसाब और उसकी वसूली इस प्रकरण का मूल विषय है,किसी भी नई जांच या बहाली के निर्णय से यह सवाल समाप्त नहीं हो सकता।

सीईओ श्रीकांत चंद्राकर से सीधे सवाल-

इस पूरे घटनाक्रम ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं,सवाल यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अधिकार क्यों दिया गया,कानून और सेवा नियमों के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए, सवाल यह है कि उस प्रक्रिया के बाद क्या निर्णय लिया गया और उसका आधार क्या है?

सीईओ श्रीकांत चंद्राकर के फैसले पर सवाल,आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी?

इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार बहाली की प्रक्रिया में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है,ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीईओ चंद्राकर को ऐसा कौन-सा आधार मिला,जिसके तहत पूर्व में बर्खास्त कर्मचारी को फिर से सेवा में लेने का निर्णय लिया गया? क्या उन्हें पुराने जांच प्रतिवेदन में कोई गंभीर कमी मिली? क्या कर्मचारी को किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी से राहत मिली? क्या बैंक की सेवा नियमावली बहाली की अनुमति देती है? क्या इस निर्णय से पहले बैंक के बोर्ड, सक्षम समिति या उच्च अधिकारियों की स्वीकृति ली गई? यदि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन हुआ है,तो बैंक प्रबंधन को आदेश और उसके आधार सार्वजनिक करने चाहिए। लेकिन यदि बहाली केवल आंतरिक स्तर पर तैयार की गई प्रक्रिया के आधार पर हुई है,तो इसकी निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है।

दैनिक घटती-घटना ने पहले ही जताई थी आशंका

इस पूरे प्रकरण को लेकर दैनिक घटती-घटना ने पहले भी लगातार खबरें प्रकाशित कर बैंक प्रबंधन और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे,9 मार्च 2026 को दैनिक घटती-घटना में इस मामले को प्रमुखता से उठाते हुए 'सहकारी बैंक में संरक्षण का संदेह?' शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद 18 अगस्त 2026 और 19 अगस्त 2026 को भी इस प्रकरण से जुड़े घटनाक्रम,दोबारा जांच की कथित कवायद और पुराने निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए खबरें प्रकाशित की गईं,उस समय मुख्य सवाल यह था कि जब जिला प्रशासन की जांच में अनियमितता सामने आ चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और बैंक ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी कर दी थी,तो फिर उसी मामले में दोबारा जांच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इस नई प्रक्रिया का उद्देश्य केवल कर्मचारी को बचाव का अवसर देना था या इससे सेवा में वापसी का रास्ता भी तैयार हो सकता था? उस समय विभागीय स्तर पर चर्चा थी कि बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर के स्तर से मामले की दोबारा जांच कराने की कवायद की जा रही है,यह भी बताया जा रहा था कि भैयाथान और सूरजपुर शाखा के शाखा प्रबंधकों को जांच की जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है,इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी,लेकिन अब नवंबर 2026 में जगदीश प्रसाद कुशवाहा की कथित बहाली की खबर सामने आने के बाद पहले उठाए गए सवाल फिर चर्चा में आ गए हैं,सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगस्त में जिस कथित जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे,उसी का परिणाम अब सेवा में वापसी के रूप में सामने आया है? यदि ऐसा है तो उस जांच की रिपोर्ट कहां है और उसके निष्कर्ष क्या हैं?


भाग-2 सीईओ चंद्राकर की नई जांच पर बड़ा सवाल 'री-एंट्री' की रहस्यमयी तैयारी?
पहले जांच में दोषी,फिर एफआईआर और सेवा समाप्ति...अब चुपके से 'री-एंट्री' की तैयारी? 35.78 लाख के फसल बीमा मामले में सीईओ चंद्राकर की नई कवायद


35.78 लाख गबन केस: घोटाला बरकरार, कार्यवाही शून्य! दोषी कौन?
अब तय होना चाहिए

बैंक के सीईओ को स्पष्ट करना चाहिए...

1. क्या जगदीश प्रसाद कुशवाहा को नवंबर 2026 में वास्तव में बहाल किया गया है?
2. यदि बहाली हुई है तो आदेश किस तारीख को और किस क्रमांक से जारी किया गया?
3. क्या बहाली का आदेश बैंक के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है?
4. क्या 23 जनवरी 2026 के संयुक्त पंजीयक आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है?
5. क्या नई जांच समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो उसका लिखित आदेश और जांच प्रतिवेदन कहां है?
6. क्या नई जांच में 5 जून 2023 के आदेश क्रमांक 383 में दर्ज निष्कर्षों पर पुनर्विचार किया गया?
7. क्या पुरानी जांच रिपोर्ट को किसी सक्षम प्राधिकारी ने निरस्त या संशोधित किया है?
8. क्या संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और पुलिस प्रकरण की वर्तमान स्थिति का परीक्षण किया गया?
9. 35.78 लाख रुपये की राशि में से अब तक कितनी वसूली हुई है?
10. क्या प्रभावित किसानों को उनकी फसल बीमा राशि वापस की गई है?

सहकारिता व्यवस्था में पारदर्शिता का सवाल

सहकारी बैंक किसानों की आर्थिक गतिविधियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ संस्थान है,यहां पदों पर बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन या बहाली तक सीमित नहीं है,बल्कि किसानों के हितों और बैंक की वित्तीय जवाबदेही को सुरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई हुई और बाद में उसे नियमों के तहत राहत मिली है,तो उस प्रक्रिया को सार्वजनिक करने में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए,लेकिन यदि बहाली का आदेश ही सामने नहीं आता,नई जांच का प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं होता और 35.78 लाख रुपये की राशि का हिसाब भी स्पष्ट नहीं किया जाता,तो सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है,यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किसी कर्मचारी की बहाली का अर्थ यह नहीं है कि उसके विरुद्ध दर्ज पुलिस प्रकरण स्वतः समाप्त हो गया या वित्तीय अनियमितता का सवाल खत्म हो गया,विभागीय सेवा संबंधी निर्णय और आपराधिक प्रकरण की स्थिति अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं से तय होती है,इसलिए बैंक प्रबंधन को दोनों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

CMYK



पोते यथरा के साथ स्टाइलिश अंदाज में नजर आए रजनीकांत

सुपरस्टार रजनीकांत को अपने पोते यात्रा के साथ एक यादगार तस्वीर के लिए पोज़ देते हुए देखा गया। रजनीकांत की बड़ी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक फोटो शेयर की, जिसमें थलाइवा और यात्रा एक साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। दादा-पोते की यह जोड़ी एक साथ पोज़ देते हुए बेहद स्टाइलिश लग रही थी। थलाइवा ने भूरे रंग की टी-शर्ट और काली पैंट पहनी थी,साथ ही उन्होंने एक काली स्पोर्ट्स कैप भी लगाई हुई थी। वहीं,यात्रा पूरी तरह से सफेद कपड़ों में अपने दादा के साथ नज़र आए। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि यात्रा,ऐश्वर्या और मशहूर अभिनेता धनुष के बड़े बेटे हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 2006 को हुआ था। इस जोड़े का एक और बेटा भी है, लिंगा राजा, जिसका जन्म 2010 में हुआ था। गौरतलब है कि 18 साल की शादी के बाद ऐश्वर्या और धनुष अलग हो गए हैं। इस बीच,हाल ही में रजनीकांत ने ग्रीस में अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताया। मंगलवार को,रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थलाइवा की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर पूरे परिवार की कुछ तस्वीरें शेयर कीं,जिनमें एथेंस (ग्रीस) में टहलते हुए रजनीकांत भी नज़र आ रहे हैं। इन यादों को शेयर करते हुए सौंदर्या ने लिखा, एथेंस में हमने कितनी शानदार यादें बनाई हैं! (तीन लाल दिल वाले इमोजी) इस प्यारे पारिवारिक ट्रिप के हर पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं। रजनीकांत और उनका पूरा परिवार अपने रिश्तेदार और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर की शादी में शामिल होने के लिए ग्रीस गए थे। अनिरुद्ध रविचंदर ने इस साल 11 नवंबर को एक भव्य समारोह में काव्या मारन से शादी की। काव्या मारन, सन ग्रूप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं और आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन हैं। ग्रीस में दो दिनों तक चली इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं।



समीरा रेड्डी का बड़ा बयान,बोलीं... बॉलीवुड से ज्यादा साउथ ने दिया सम्मान

बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने अपने फिल्मी करियर और निजी जीवन को लेकर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हिंदी सिनेमा की तुलना में दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका अनुभव कहीं ज्यादा शानदार रहा। समीरा के मुताबिक, साउथ सिनेमा में उन्हें बॉलीवुड से अधिक सम्मान, पैसा,स्टारडम और दर्शकों का प्यार मिला। उन्होंने फिल्मी दुनिया से लंबे ब्रेक,संजय दत्त के साथ वापसी और बच्चों की परवरिश के बीच काम करने की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। अभिनेत्री के इन बयानों के बाद बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के अनुभवों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

उसके आने से किस्मत बदल गई,कभी 70 घंटे तक बिना सोए काम करते थे आदित्य धर,20 साल की मेहनत के बाद मिली पहचान,अब यामी को बताया लेडी लक

आदित्य धर ने यामी गौतम को अपना लेडी लक बताया। वहीं यामी ने पति की ईमानदारी,संघर्ष, मेहनत और काम के प्रति जुनून की जमकर तारीफ की। बॉलीवुड के चर्चित निर्देशक आदित्य धर और एक्ट्रेस यामी गौतम की जोड़ी अक्सर अपनी शानदार केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में रहती है। दोनों एक-दूसरे के काम और मेहनत की खुलकर तारीफ करते हैं। हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2026 के मंच पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान आदित्य धर ने अपनी सफलता के पीछे यामी गौतम के साथ को खास बताया और उन्हें अपनी लेडी लक कहा। वहीं यामी ने भी पति की तारीफ करते हुए उनके संघर्ष,ईमानदारी और काम के प्रति जुनून के बारे में कई दिलचस्प बातें साझा कीं।

रातोंरात मिली सफलता के पीछे 20 साल की मेहनत है

कार्यक्रम के दौरान आदित्य धर ने अपनी अब तक की पेशेवर यात्रा पर बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को भले ही उनकी सफलता रातोंरात मिली हुई लगती हो, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें करीब 20 साल लगे हैं। आदित्य के मुताबिक किसी भी कामयाबी के पीछे लंबे समय का संघर्ष,धैर्य और लगातार मेहनत छिपी होती है। आदित्य धर साल 2006 में मुंबई आए थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसके अलावा वह गीतकार



और डायलॉग राइटर के रूप में भी सक्रिय रहे। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने साल 2019 में फिल्म उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक से बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाई। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्शन का नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला। हालांकि फिल्म धुरंधर की सफलता ने उन्हें देशभर में एक अलग पहचान दिलाई।

यामी को बताया अपनी लेडी लक

आदित्य ने इस दौरान अपनी पत्नी यामी गौतम को अपनी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि जब से यामी उनकी जिंदगी में आई हैं, उनकी किस्मत बदल गई है। निर्देशक ने यामी को अपना लेडी लक बताते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी से उन्हें भारतीय कहानियों को दुनिया के सामने पेश करने की प्रेरणा और ताकत मिलती है। आदित्य ने यामी की तारीफ करते हुए उन्हें गोल्डन हार्ट वाली इंसान भी बताया। उन्होंने कहा कि दर्शकों ने अभी तक यामी की प्रतिभा का 50 फीसदी हिस्सा भी नहीं देखा है। निर्देशक को आर्टिकल 370 और हक जैसी फिल्मों में यामी का काम काफी पसंद आया। उन्होंने यह भी कहा कि वह यामी के आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें भरोसा है कि अभिनेत्री के भीतर अभी बहुत कुछ ऐसा है,जो दर्शकों के सामने आना बाकी है।

यामी ने बताया,आदित्य की सबसे बड़ी खूबी क्या है?

वहीं यामी गौतम ने भी पति आदित्य धर की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आदित्य की सबसे बड़ी खूबी उनकी ईमानदारी, मजबूत चरित्र और अपने काम के प्रति जुनून है। यामी के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करने के बावजूद आदित्य ने कभी अपने भीतर कड़वाहट नहीं आने दी। अभिनेत्री ने बताया कि आदित्य किसी के बारे में बुरा बोलना पसंद नहीं करते। वह अपने काम को लेकर बेहद समर्पित हैं और सेट पर कई बार लगातार 70 घंटे तक बिना सोए काम कर चुके हैं। यामी ने उनके विजन,मेहनत और साहस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके मुताबिक आदित्य की यही खूबियां उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं।

पत्नी के साथ काम करते समय प्रोफेशनल रहते हैं आदित्य

कार्यक्रम में आदित्य से यह भी पूछा गया कि क्या वह अपनी पत्नी यामी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए घर पर ही ऑफर दे देते हैं। इस पर निर्देशक ने बताया कि उनके लिए काम और निजी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट सीमा है। वह घर पर अनौपचारिक तरीके से किसी फिल्म का प्रस्ताव रखने के बजाय पेशेवर बातचीत को प्राथमिकता देते हैं। आदित्य ने कहा कि उनके लिए काम की अपनी एक गरिमा है और वह इसे बेहद सम्मान के साथ देखते हैं। उन्होंने काम को मां सरस्वती से जुड़ी पवित्र चीज की तरह बताया। इसलिए यामी के साथ काम करने के मामले में भी वह पेशेवर प्रक्रिया का पालन करना पसंद करते हैं।

2021 में हुई थी शादी, एक बेटे के माता-पिता हैं दोनों

बता दें कि आदित्य धर और यामी गौतम ने 4 जून 2021 को हिमाचल प्रदेश में एक निजी समारोह में शादी की थी। दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखा था और शादी की तस्वीरें साझा कर फैंस को इसकी जानकारी दी थी। मई 2024 में उनके घर बेटे वेदाविद का जन्म हुआ।



ब्रेकअप के बाद भी कायम है ईशा देओल और भरत तख्तानी की दोस्ती,तलाक के दो साल बाद फिर दिखे साथ

ईशा देओल की फिल्म प्रताप की स्क्रीनिंग में उनके एक्स-हसबैंड भरत तख्तानी भी पहुंचे। दोनों ने परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन इस दौरान हेमा मालिनी के चेहरे पर थोड़ी झिझक और असहजता नजर आई। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा देओल एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी आने वाली फिल्म प्रताप की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला,जिसने सबका ध्यान खींच लिया। दरअसल, इस खास मौके पर ईशा के साथ उनके पूर्व पति भरत तख्तानी भी नजर आए। दोनों ने लंबे समय बाद एक ही कार्यक्रम में साथ पोज दिए। इस दौरान ईशा की मां और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी और बहन अहाना देओल भी मौजूद थीं। हालांकि परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाते समय हेमा मालिनी के चेहरे पर थोड़ी झिझक और असहजता नजर आई। बता दें, पहले भी भरत और ईशा साथ नजर आ चुके हैं।

फिल्म स्क्रीनिंग में साथ दिखे ईशा और भरत

मुंबई में गुरुवार को ईशा देओल की फिल्म प्रताप की स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस मौके पर ईशा गोल्डन रंग की सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं। साड़ी पर बारीक प्रिंट और जरी का काम उनके लुक को खास बना रहा था। वहीं,भरत तख्तानी कैजुअल अंदाज में कार्यक्रम में पहुंचे। हेमा मालिनी इस दौरान हल्के पीच-पिंक रंग की साड़ी, गले में नेकलेस और माथे पर बिंदी लगाए दिखाई दीं। स्क्रीनिंग के दौरान भरत ईशा और उनके परिवार के साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। खास बात यह रही कि दोनों के तलाक के ऐलान के करीब दो साल बाद भी उनके बीच सहजता दिखाई दी। हालांकि, फैमिली फोटो के दौरान हेमा मालिनी थोड़ी संकोच करती नजर आईं। भरत और ईशा के बीच खड़ी हेमा के हावभाव ने कैमरों का ध्यान खींचा।

स्कूल के दिनों में शुरू हुई थी ईशा-भरत की प्रेम कहानी

ईशा देओल और भरत तख्तानी की कहानी काफी पुरानी है। दोनों की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में मुंबई में इंटर-स्कूल प्रतियोगिताओं के दौरान हुई थी। भरत ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब वह करीब 13 साल के थे,तभी उन्हें ईशा पर क्रश हो गया था। उन्होंने ईशा को अपना पहला प्यार भी बताया था। हालांकि किशोरावस्था में शुरू हुआ उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और कुछ समय के लिए दोनों की बातचीत भी बंद हो गई थी। कई साल बाद उनकी दोबारा मुलाकात हुई और फिर दोनों ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया। इसके बाद 29 जून 2012 को मुंबई के इस्कॉन मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय रीति-रिवाजों से दोनों की शादी हुई।

11 साल की शादी के बाद लिया था अलग होने का फैसला

शादी के बाद ईशा और भरत दो बेटियों के माता-पिता बने। उनकी बड़ी बेटी राध्या का जन्म 2017 में हुआ,जबकि छोटी बेटी मिराया 2019 में पैदा हुई। करीब 11 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद फरवरी 2024 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया। अपने साझा बयान में उन्होंने बताया था कि वे आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ किया था कि उनकी बेटियों की परवरिश और खुशी उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। अलग होने के बावजूद ईशा और भरत के बीच कड़वाहट की खबरें सामने नहीं आईं। दोनों कई मौकों पर साथ नजर आए हैं।

खेल-समाचार

बांग्लादेश वनडे सीरीज में केशव महाराज को दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी



जोहानसबर्ग,20नवम्बर 2026। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका की एक ऐसी टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें मुख्य खिलाड़ियों की जगह कई नए या कम अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली इस वनडे सीरीज के लिए कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। नियमित कप्तान टेम्बा बावुमा और टी 20 आई कप्तान एडेन मार्करम उन प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें आराम दिया गया है,इसलिए टीम की कमान केशव महाराज संभालेंगे।

भारत-पाकिस्तान टक्कर 22 नवम्बर को

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में होगा मुकाबला

दोहा,20नवम्बर 2026। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की ए टीमों के बीच टक्कर होने वाली है। एक सप्ताह में भारत-पाकिस्तान का ये दूसरा क्रिकेट मुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और महामुकाबले का मंच सजकर तैयार है। इस बार दोनों देशों की ए टीमें आमने सामने होने जा रही हैं। ये मैच एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में खेला जाएगा, जोकि 50 ओवर का टूर्नामेंट है। करीब एक सप्ताह के भीतर ही दोनों टीमें फिर से टकराने जा रही हैं। इस मैच को आप अपने टीवी और मोबाइल पर लाइव कैसे देख पाएंगे, ये जान लीजिए। मुकाबला 22 नवंबर को दोहा में होना है।

तिलक वर्मा कर रहे हैं भारतीय टीम की कप्तानी,पाकिस्तान टीम की कमान अब्दुल समद के हाथ में है...

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत ए और पाकिस्तान ए की टीमें आपस में टकराने वाली हैं। भारतीय टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की कमान अब्दुल समद के पास है। मजे की बात ये है कि पाकिस्तान की टीम से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं,जो अभी कुछ ही दिन पहले



भारत की अंडर 19 टीम से एशिया कप के फाइनल में हार चुके हैं। जब भारत ने पाकिस्तान को एक रोचक मुकाबले में एक विकेट से पीटने का काम किया था। उस टीम के कप्तान फरहान यूसुफ भी इस ए टीम के स्क्वाड में शामिल हैं। इस टूर्नामेंट यानी एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मीडिया राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। यानी अगर आप टीवी पर मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स पर इसे देख सकते हैं। मैच को मोबाइल पर देखने के लिए आपको सोनी लिव एप पर जाना होगा। टेबलेट और लैपटॉप पर भी इस मैच को सोनी लिव एप से ही लाइव देखा जा सकेगा। मैच का वेन्यू दोहा है। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद साढ़े तीन बजे से शुरू होगा,इससे आधे घंटे पहले तीन बजे दोनों कप्तान बीच मैदान में टॉस के लिए आएंगे।

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी पर रहेगी नजर

जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस मैच में भारत की कप्तानी तिलक वर्मा को दी गई है,लेकिन सभी की नजर वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर रहने वाली है। टीम में प्रभसिमरन सिंह को भी मौका दिया गया है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि वैभव और अभिषेक की जोड़ी एक बार फिर से ओपनिंग करती हुई दिखाई देगी। गेंदाबाजी में हर्षित राणा के खेल पर नजर होगी,जोकि इंजरी से वापसी कर रहे हैं। भारत के लिए मिडिल आर्डर में कप्तान तिलक वर्मा,आयुष बडोनी,कुमार कुशाग्र और सूर्यांश शेडगे होंगे,वहीं फिनिशिंग की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर आ सकती है। हर्षित राणा के अलावा भारतीय टीम में प्रिंस यादव, तनुश कोटियन,हर्ष दुबे और अरशद खान अलावा शाहबाज अहमद भी हैं।

भारत ए का पूरा स्क्वाडः अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, तिलक वर्मा (कप्तान),आयुष बडोनी,रिंकू सिंह,कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर),शाहबाज अहमद,सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम,हर्षित राणा,अरशद खान,प्रिंस यादव,तनुश कोटियन, हर्ष दुबे।

पाकिस्तान ए का पूरा स्क्वाडः शाहजैब खान,हैदर अली,अब्दुल समद (कप्तान),हसन नवाज,माज सदाकत,दानिश अजीज,मोहम्मद इमरान रंधावा,रोहेल नजीर (विकेट कीपर),मोहम्मद हसनैन,सुफयान मोकिम, अहमद दानियाल,अली रजा, साद मसूद,शमील हुसैन,फरहान यूसुफ।

न्यायालय तहसीलदार दरिमा, जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा0प्र0क0/अ-62/2026-27
ग्राम बडादमाली

एतद् सर्व साधारण ग्राम बडादमाली को सूचित किया जाता है कि आवेदक मेगन किण्डो आ0 स्व. मंगलू उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बडादमाली तहसील दरिमा जिला सरगुजा (छ0ग0) द्वारा ग्राम बडादमाली प0ह0नं0 17 स्थित अपने अधिपत्य व स्वामित्व की भूमि ख0नं0 264 रकबा 1.133 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज होना बताया है। उक्त वर्णित भूमि ख0न0 में आवेदक के द्वारा 500 नग सागौन का वृक्ष का रोपण किया गया है, जिसमे से 200 पेड की लम्बाई व चौडाई होने के कारण अगल-बगल में जो कृषि भूमि है, जिसमें धूप नहीं पडने के कारण फसल का उत्पादन कम होने से 200 वृक्षों को कटवाकर नये वृक्ष लगवाने की अनुमति हेतु आवेदन न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर के समक्ष आवेदन पेश किया है। जो जांच प्रतिवेदन हेतु मूल प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त कार्यवाही से यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपना आक्षेप स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 23/11/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 02/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से अंकित कर जारी किया गया।

सील

तहसीलदार
दरिमा,जिला-सरगुजा



विराट कोहली के बड़े फैन आर्यवीर सहवाग टीम के लिए तैयार

नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। भारत के युवा बल्लेबाज आर्यवीर सहवाग ने अपनी बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को अपनी मुख्य प्रेरणा बताया है। उन्होंने कहा कि वह खुद को किसी एक खास तरह की बल्लेबाजी शैली तक सीमित रखने के बजाय, मैच की स्थितियों के अनुसार ढलना और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना चाहते हैं। भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे,आर्यवीर ने ओमान में खेले गए,छ्ष्ट अंडर-19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे; उन्होंने 5 मैचों में 361 रन बनाए,जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की और अपना नौवां खिताब जीता। आर्यवीर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 10 नवंबर को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ रहा। उन्होंने 168 गेंदों पर शानदार 160 रन बनाए,जिसमें 17 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की मदद से भारत 309/7 का स्कोर खड़ा कर सका।

लियोनल मेसी सबसे महंगे खिलाड़ी

नई दिल्ली,20 नवम्बर 2026। फुटबॉल की दुनिया में लियोनेल मेसी का जलवा सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। कमाई के मामले में भी वह बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे हैं। मेजर लीग सॉकर की 2026 की नई सैलरी रिपोर्ट में मेसी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं, बार्सिलोना के पूर्व स्टार रॉबर्ट लेवांडोस्की ने इस सूची में दूसरा और फ्रांस के एंटोनी ग्रिजमैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है।मेजर लीग सॉकर प्लेयर्स एसोसिएशन की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इंटर मियामी के कप्तान मेसी को सालाना 28.33 मिलियन डॉलर यानी करीब 263.43 करोड़ रुपये की गारंटीड राशि मिलती है। इस रकम में बेस सैलरी और गारंटीड बोनस शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले उनकी गारंटीड कमाई में करीब 8 मिलियन डॉलर (74.40 करोड़ रुपये) का इजाफा हुआ है।

लेवांडोस्की और ग्रिजमैन भी टॉप-3 में शामिल

इस साल समर ट्रांसफर विंडो में मेजर लीग सॉकर से जुड़ने वाले बड़े सितारों में रॉबर्ट लेवांडोस्की और एंटोनी ग्रिजमैन भी शामिल हैं। शिकागो फायर से खेलने वाले पोलैंड के स्ट्राइकर लेवांडोस्की 19.51 मिलियन डॉलर की गारंटीड कमाई के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उनकी बेस सैलरी 16 मिलियन डॉलर है। वहीं, ऑरलैंडो सिटी के लिए खेलने वाले फ्रांस के ग्रिजमैन 13.93 मिलियन डॉलर की गारंटीड राशि के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उनकी



बेस सैलरी करीब 10.44 मिलियन डॉलर है। ग्रिजमैन ने एटलेटिको मैड्रिड छोड़कर मेजर लीग सॉकर का रुख किया था।

इंटर मियामी खिलाड़ियों पर खर्च करने में सबसे आगे

सिर्फ खिलाड़ियों की व्यक्तिगत कमाई ही नहीं, बल्कि टीमों के कुल वेतन खर्च में भी इंटर मियामी सबसे आगे है। क्लब अपने खिलाड़ियों को कुल 59.37 मिलियन डॉलर की गारंटीड राशि देता है। शिकागो फायर 41.29 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे और अटलांटा यूनाइटेड 38.35 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद ला गैलेक्सी 34.91 मिलियन डॉलर और एलएएफसी 32.91 मिलियन डॉलर के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेजर लीग सॉकर में सबसे कम वेतन खर्च करने वाली टीम फिलाडेल्फिया यूनियन है, जिसका कुल गारंटीड पे-रोल 12.64 मिलियन डॉलर है।

मेजर लीग सॉकर में खिलाड़ियों की कमाई में हुआ इजाफा

मेजर लीग सॉकर में खिलाड़ियों की औसत गारंटीड कमाई बढ़कर 746,936 डॉलर हो गई है। पिछले साल यह आंकड़ा 632,809 डॉलर था। यानी इसमें करीब 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, लीग में कम से कम 1 मिलियन डॉलर सालाना गारंटीड कमाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़कर 150 हो गई है। मई 2026 में यह संख्या 133 थी। इस रिपोर्ट से साफ है कि मेजर लीग सॉकर दुनिया के बड़े फुटबॉल सितारों को आकर्षित करने के साथ-साथ खिलाड़ियों पर अपना खर्च भी लगातार बढ़ा रही है। हालांकि, कमाई के मामले में फिलहाल मेसी के आसपास कोई दूसरा खिलाड़ी नजर नहीं आता।

CMYK

छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

तूफान अकवान से बदला मौसम,रायपुर में बूंदाबांदी



रायपुर,20 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर देखा जा रहा है। रायपुर में मौसम बदला। ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू हुई। तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने से शहर में कुछ जगह लोग अलाव जलाकर आग तापते नजर आए। वहीं, अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान बलरामपुर, जांजगीर-चांपा,जशपुर,रायगढ़,सक्ती,सारंगढ़-बिलाईगढ़ और सरगुजा जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में बना है चक्रवाती तूफान

चक्रवाती तूफान 'अकवान' दोपहर उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इसके गोपालपुर के पास तट पार करने की संभावना है। इस दौरान 90 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी,जबकि झोंकों की रफ्तार 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में भी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश में क स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं, एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज-चमक,बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

हैदराबाद के पब में पार्टनर बनाने का झांसा,3.42 करोड़ ठगे...

बिलासपुर के 3 कारोबारियों से फेक एग्रीमेंट किया

बिलासपुर,20 नवम्बर 2026। बिलासपुर के तीन कारोबारियों से हैदराबाद के डियाब्लो रेस्टोरेंट और पब में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने के नाम पर 3 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयवीर सिंह सभरवाल और शेषम कौर ने कारोबारियों से पार्टनर बनाने का समझौता किया और किस्तों में पैसे ले लिए। लेकिन न तो उन्हें कंपनी में पार्टनर बनाया और न ही निवेश की जानकारी दी। शिकायत के बाद तारबाहर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है। लिंक रोड के शिखर सराफ (38) ने पुलिस को बताया कि साल 2022 में बिलासपुर में गायक सुखविंदर सिंह का कार्यक्रम हुआ था। इसी दौरान उनकी मुलाकात लेडीज सर्कल इंडिया की सदस्य शेषम कौर से उनके घर पर हुई। बातचीत के दौरान शेषम ने हैदराबाद में प्राशी वेंचर्स एलएलपी के तहत डियाब्लो पब शुरू करने की जानकारी दी। इसके बाद शेषम कौर और जयवीर सिंह सभरवाल ने खुद को कंपनी का अधिकृत पार्टनर बताते हुए शिखर सराफ और उनके साथी रितेश शाह को पब में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का ऑफर दिया। दोनों कारोबारी इस नए बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। शिकायत के मुताबिक, 10 जनवरी 2025 को दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद तीन कारोबारियों ने किस्तों में कंपनी के हैदराबाद स्थित खाते में ऋलतस के जरिए रकम ट्रांसफर की। इसमें शिखर सराफ ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए, रितेश शाह ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए और रितेश के साले सक्षम श्रीवास्तव ने 62 लाख 50 हजार रुपए दिए। इस तरह तीनों ने कुल 3 करोड़ 42 लाख 50 हजार रुपए निवेश किए।



पीएम स्वनिधि योजना में छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार,फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में पहला स्थान

राज्य स्तरीय इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान,उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किए राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर,20 नवम्बर 2026। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' में छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

राज्य ने फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य स्तरीय दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किए। समारोह में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया द्य समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहे।

पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा,संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास निलेश महादेव क्षीरसागर तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मिशन) सुनील अग्रहरी भी उपस्थित रहे। स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026 के अंतर्गत डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिका परिषद बड़े बचेली ने देश में प्रथम और नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, एक लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों की श्रेणी में नगर पालिक निगम बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेनदेन से जोड़ने, संस्थागत ऋण सुविधा उपलब्ध कराने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से फास्टेस्ट मूवर्स श्रेणी में देश में प्रथम स्थान और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करना राज्य में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचारों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। पथ विक्रेताओं और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यह राष्ट्रीय सम्मान राज्य में सुशासन,प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को राज्य स्तर पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार तथा बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा को डिजिटल अडॉप्शन श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिलना नगरीय निकायों की बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल लेनदेन और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने की प्रेरणा देगी। इस अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी एवं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे,नगर पालिका परिषद दंतेवाड़ा की अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार ध्रुव तथा नगर पालिका परिषद बड़े बचेली के अध्यक्ष राजू जायसवाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.टी.एम.कृष्णा राव भी उपस्थित रहे।



सीएम ने कहा...छोटे कारोबारियों को मिल रहा आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ को पांच राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह योजना के बेहतर क्रियान्वयन और नए प्रयासों का नतीजा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राज्य और नगरीय निकायों को मिले ये पुरस्कार अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों का परिणाम है। योजना के जरिए पथ विक्रेताओं को बैंक से कर्ज,डिजिटल भुगतान और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।

चक्रवात से फसल खराब हुई तो सरकार देगी मुआवजा

सीएम साय बोले...किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं,कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए

रायपुर,20 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में चक्रवात अकवान के असर से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी धान और रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को राहत देने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को फसल नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। नुकसान की पुष्टि होने पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 और फसल बीमा के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि चक्रवात के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान होगा, उनका सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इससे पहले भी चक्रवात के कारण फसलों को नुकसान हुआ था। उस समय भी सरकार ने सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को सहायता दी थी। इस बार भी नुकसान का आकलन कर किसानों को राहत दी जाएगी।

यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी जाएंगे : उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाए जाने के सवाल पर सीएम साय ने कहा कि चुनाव के दौरान अलग-अलग राज्यों के कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों में जाकर सहयोग करते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता जाएंगे।



भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संध्या

मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे के बारे में बताया कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए वे दिल्ली जा रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं, प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की झलक दिखाएंगे।

गृहमंत्री बोले...सीएम की पत्नी और मेरी भी सुरक्षा घटाई...सिक्योरिटी में कटौती पर पूर्व सीएम भूपेश बोले...भेदभाव न हो,प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

दुर्ग-भिलाई,20 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में नेताओं की सुरक्षा कम करने के फैसले पर गृहमंत्री विजय शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने-सामने आ गए हैं। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब नेताओं को पहले जैसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। इसलिए सुरक्षा में एक श्रेणी की कटौती की जा रही है।

वहीं,भूपेश बघेल ने कहा कि सुरक्षा कम करने में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए तय नियमों और प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। दरअसल, दीपावली मिलन कार्यक्रम में गृहमंत्री विजय शर्मा से नेताओं की सुरक्षा कम करने को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। अब नक्सली कैडर का कोई ऐसा समूह नहीं है, जो एक साथ घूमकर वारदातों को अंजाम दे सके। इसलिए अब पहले जैसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। गृहमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले ही यह काम पूरा कर लिया गया था। इसके बाद भी एहतियात के तौर पर 6 महीने तक सुरक्षा में कटौती का फैसला रोककर रखा गया। इस दौरान किसी तरह की परेशानी सामने नहीं आई। उन्होंने साफ किया कि नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह नहीं हटाई जा रही है, बल्कि जिन लोगों को जेड प्लस जैसी सुरक्षा मिली हुई है, उनकी सुरक्षा एक श्रेणी कम की जा रही है। जहां सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी, वहां इसे हटा दिया जाएगा। भूपेश बघेल की सुरक्षा कम किए जाने के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी की सुरक्षा भी कम की गई है।



छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रभारी सचिव बने जितेंद्र बघेल-हरनाम सिंह

देवेंद्र प्रभार मुक्त,पाढ़ी ओडिशा,नरेश गुजरात संभालेंगे,भाजपा बोली-गुटबाजी का असर

रायपुर,20 नवम्बर 2026। कांग्रेस ने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 81 सचिवों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों में बदलाव की सूची जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव भी बदल दिए गए हैं। अब जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले यह जिम्मेदारी विजय जांगिड और एसए संपत कुमार संभाल रहे थे। वहीं,जरिता लैतफलांग को छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त कर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल में छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। कोको पाढ़ी को ओडिशा और नरेश ठाकुर को गुजरात का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने नई नियुक्तियों को लेकर प्रेस रिलीज जारी की है। पार्टी के मुताबिक,सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इस फेरबदल को भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा बताया है।



कोको पाढ़ी को ओडिशा,नरेश ठाकुर को गुजरात की जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ के नेता कोको पाढ़ी को ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी सचिव बनाया गया है। वहीं,नरेश ठाकुर को गुजरात पीसीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह जितेंद्र बघेल और हरनाम सिंह छत्तीसगढ़ में संगठन का काम देखेंगे,जबकि कोको पाढ़ी और नरेश ठाकुर दूसरे राज्यों में पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

देवेंद्र यादव समेत 25 नेताओं को हटाया : फेरबदल के तहत भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव को AICC सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वे गुजरात पीसीसी के प्रभारी सचिव थे। उनके अलावा विजय जांगिड और एसए संपत कुमार समेत कुल 25 सचिवों और संयुक्त सचिवों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाया गया है।

कई राज्यों और विभागों में भी बदलाव : AICC की नई सूची में मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेश,महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात,बिहार, झारखंड,ओडिशा,पंजाब, हरियाणा,कर्नाटक,केरल,असम,तेलंगाना और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में नई नियुक्तियां की गई हैं। राज्यों के अलावा संचार,प्रचार-प्रसार, मीडिया,सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया विभागों में भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। पार्टी ने सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

24 साल पुराने एकतरफा बंटवारे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला...पैतृक संपत्ति में बेटी को मिलेगा एक तिहाई हिस्सा

बिलासपुर,20 नवम्बर 2026। हाईकोर्ट ने 24 साल पहले किए गए एकतरफा बंटवारे को अवैधानिक माना है। कोर्ट ने फैसला दिया कि पैतृक संपत्ति में बेटी को भी पूरा अधिकार है और उसको हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा केवल इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि उसके चाचाओं ने उसे शामिल किए बिना जमीन का बंटवारा करा लिया था। कोर्ट ने जशपुर जिले के एक पारिवारिक जमीन विवाद में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए महिला के एक तिहाई हिस्से का अधिकार बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि महिला 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में हुए संशोधन के आधार पर सहदायिक के रूप में हिस्सा नहीं मांग रही है, बल्कि अपने दिवंगत पिता के हिस्से की उत्तराधिकारी होने के नाते दावा कर रही है। जस्टिस सुषमा सावंत ने चाचाओं के वारिसों की दूसरी अपील खारिज कर विचारण न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा। मामला जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के अंबाचुआ गांव की 14.15 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। ऋखी मुनी बाई ने दावा किया था कि वह स्वर्गीय विश्वनाथ राम की बेटी है। विश्वनाथ राम की मृत्यु उनके जन्म के करीब एक महीने बाद हो गई थी। महिला का कहना था कि पिता के हिस्से की जमीन पर उसका भी अधिकार है, लेकिन दोनों चाचा ने 31 अगस्त 2002 को राजस्व न्यायालय से बंटवारा कराते समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया। चाचा ने 17 मई 2009 को लिखित समझौते में उसके पिता से संबंध स्वीकार किए थे। इसके बावजूद जमीन में हिस्सा नहीं दिया गया। महिला ने 2011 में बंटवारा,स्वामित्व की घोषणा और कब्जा दिलाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने उसे जमीन का एक तिहाई हिस्सा देने का फैसला सुनाया। प्रथम अपीलीय अदालत ने भी इसे सही ठहराया था।

चाचाओं ने अदालत में दावा किया कि विश्वनाथ राम की कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी सुगंती देवी दोबारा विवाह कर अपने मायके चली गई थीं। उन्होंने 2002 के बंटवारे और मुकदमे की समय-सीमा पर भी सवाल उठाए।



ऑनलाइन सट्टा-हवाला नेटवर्क...25 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले,8 लाख कैश, गहने-महंगी घड़ियां जब्त

बिलासपुर,20 नवम्बर 2026। बिलासपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे और हवाला के जरिए करोड़ों का अवैध कारोबार करने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि सट्टे से कमाई गई रकम हवाला के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजी गई। इस रकम से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई गई। नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े हैं और वहां भी संपत्ति होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारकर करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के गहने, महंगी घड़ियां और बैंकिंग दस्तावेज जब्त किए हैं। तलाशी में 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत का पता लगाकर कुर्की की तैयारी कर रही है। 3 आरोपी सुनील रोहरा, मनीष रोहरा और जबलपुर निवासी आकाश गोगा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

सट्टे की कमाई से बनाई करोड़ों की संपत्ति : पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे से मिलने वाली रकम को हवाला के जरिए अलग-अलग जगह भेजा जाता था। इस रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया। जांच में देश के कई राज्यों में सट्टे की रकम के लेन-देन की जानकारी मिली है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन की जांच कर रही है।

दुबई तक फैला नेटवर्क, विदेश में भी संपत्ति : जांच में नेटवर्क के तार दुबई तक जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस को पता चला है कि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने विदेश में भी संपत्तियां बनाई हैं। इसे देखते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। इससे आरोपियों के देश छोड़कर जाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। वहीं, विदेश में मौजूद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

तलाशी में 8 लाख कैश, गहने और महंगी घड़ियां मिलीं : पुलिस ने 13 नवंबर को संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान करीब 8 लाख रुपए कैश, सोने के आभूषण, महंगी घड़ियां और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े दस्तावेज मिले। इसके साथ ही करीब 25 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों से जुड़े कागजात भी मिले हैं। पुलिस इन संपत्तियों के मालिकाना हक और इन्हें खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम के सोर्स की जांच कर रही है। पुलिस अब बैंक खातों, हवाला के जरिए हुए लेन-देन और संपत्तियों में किए गए निवेश की कड़ियां जोड़ रही है। जांच में अपराध से कमाई गई रकम से खरीदी गई संपत्तियों की पहचान की जा रही है।

इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत कुर्की की कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस का मकसद सिर्फ सट्टा चलाने वालों तक पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक नेटवर्क और इससे फायदा उठाने वालों की पहचान करना भी है।



प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)